



सब का सपना



रक्षाबंधन पर मातृशक्ति को उपहार, 560 महिलाओं को बांटी साड़ी

पेज: 4



निष्पक्ष व निडर - हिंदी दैनिक समाचार पत्र

'धुरंधर 2 के साथ लैश पर यश का बड़ा बयान

पेज: 8

वर्ष : 02

अंक : 142

गुरुवार 27 अगस्त 2026

अमरोहा (उत्तर प्रदेश)

www.sabkasapna.com

पृष्ठ : 08

मूल्य: 2 रुपए

हिमाचल में भूकंप, किचन में रखे वर्तन गिरे, सुबह-सुबह लगे झटके लोग घरों से निकले

शिमला (एजेंसी)। हिमाचल की राजधानी शिमला सहित आस पास के शहरों में आए भूकंप ने लोगों को डरा दिया। घरों की किचन में रखे वर्तन गिरने लगे। जब तक लोग समझ पाते तब तक झटके लगने लगे। लोग डर के चलते घरों से बाहर निकले तब पता चला कि भूकंप के झटके आ रहे हैं। सुबह 5 बजकर 46 मिनट और 50 सेकंड पर आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.0 दर्ज की गई। इसका केंद्र शिमला से करीब 66 किलोमीटर पूर्व-दक्षिण दिशा में, जमीन से 10 किलोमीटर नीचे जुब्बल-कोटखाई की तरफ था। यह झटका लगभग तीन सेकंड तक महसूस किया गया, जिसके दौरान धरती डोलने पर कई लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। हालांकि, उस समय कई लोग नींद में थे, जिस वजह से उन्हें इसका पता नहीं चल पाया। कुछ नागरिकों ने सोशल मीडिया के माध्यम से तैज झटका लगने की जानकारी साझा की। शिमला के अलावा सोलन, सिरमौर, बिलासपुर और मंडी के कई अन्य क्षेत्रों में भी भूकंप के झटके अनुभव किए गए।
गनीमत यह रही कि इस घटना में फिलहाल किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश भूगोलिक रूप से भूकंपों की दृष्टि से बेहद संवेदनशील राज्यों में आता है, जिसमें शिमला और मंडी जैसे जिले जिन-4 और जिन-5 के अंतर्गत आते हैं। सामान्य तौर पर 5.0 से कम तीव्रता वाले भूकंपों से बड़े पैमाने पर नुकसान की संभावना कम होती है। इससे पहले हाल ही में चंबा और कांगड़ा जिलों में भी भूकंप के झटके दर्ज किए जा चुके हैं। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है।

गोवा कैबिनेट का ऐतिहासिक कदम : गैर-कानूनी धर्मांतरण पर उम्रकैद की सजा का प्रस्ताव

पणजी (एजेंसी)। गोवा कैबिनेट ने गैर कानूनी धर्म परवर्तन निषेध विधेयक 2026 को विधानसभा में पेश करने की मंजूरी दे दी है। यह विधेयक जबरन, दबाव, लालच, धोखाधड़ी या शادی के मकसद से किए गए धर्मांतरण को रोकने के लिए कड़े प्रावधान करता है। प्रस्तावित कानून के तहत इसतरह के मामलों में दोषियों को उम्रकैद तक की सजा, न्यूनतम 50 हजार रुपये का जुर्माना और पीड़ितों को 5 लाख रुपये तक का मुआवजा देना पड़ सकता है। विधेयक प्रावधान करता है कि यदि कोई शायी केवल गैर कानूनी धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से की गई हो, तब उस शायी को अमान्य घोषित किया जा सकता है। धर्मांतरण में शामिल दोषियों को कम से कम तीन साल और अधिकतम 10 साल तक की जेल हो सकती है। यदि धर्मांतरण का शिकार कोई नाबालिग, मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति, महिला या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, तब यह सजा 5 से 14 साल की कैद और 1 लाख रुपये के जुर्माने तक बढ़ सकती है। मुख्य सचिव वी. कंडावेलु ने इस कानून के उद्देश्य पर कहा कि इसका मकसद कमजोर और भोले-भाले लोगों को अनुचित तरीकों से होने वाले धर्मांतरण से बचाना है। प्रस्तावित कानून के अनुसार, स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को कम से कम 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करना होगा, जबकि धर्मांतरण समारोह आयोजित करने वाले व्यक्ति को रस्म से एक महीने पहले जानकारी देनी होगी।

कंगना के पलटवार से सन्न बाबा रामदेव : जवानी पर सवाल उठाना पड़ा भारी

नई दिल्ली (एजेंसी)। राजनीति और मनोरंजन की दुनिया में अपने बेबाक बयानों से सुर्खियां बटोरने वाली बीजेपी सांसद कंगना रनौत और योगगुरु बाबा रामदेव के बीच छिड़ा जुबानी जंग अब व्यक्तिगत हमलों में बदल गया है। कंगना के विवादित जनरेशन गटर बयान से शुरू हुआ यह मामला, रामदेव द्वारा उनकी जवानी और अतीत पर सवाल उठाने के बाद तीखे व्यक्तिगत पलटवार में बदल गया। आंध्र के करारे जवाब से सन्न हुए रामदेव को क्षिराकार उड़ कहना पड़ा कि वह विवाद को और आगे नहीं बढ़ाना चाहते। दरअसल, जंतर-मंतर पर युवाओं को जनरेशन गटर कहने पर उठे विवाद के बीच, जब बाबा से कंगना के बयान पर सवाल पूछा गया, तब उन्होंने अभिनेत्री-सांसद पर हमला बोल दिया। रामदेव ने कहा था, ‘उनका बचपन कैसा था? उनकी जवानी कैसी थी? उनके पिछले काम कैसे थे? मैं इसतरह के लोगों पर बात नहीं करना चाहता। युवाओं को जनरेशन गटर कहना विकृत मानसिकता की निशानी है।' रामदेव के इन्हीं निजी टिप्पणियों पर सांसद कंगना ने तत्काल और तीखा जवाब दिया। उन्होंने लिखा, ‘बाबा जी, मेरी जवानी या बेडरूम के बारे में दिवास्त्रजन मत देखिए। अफवाहों और गॉसिप के आधार पर ही कुछ भी मान सकते हैं। कम से कम मुझे झूठे या ध्रामक प्रभावकारिता कम से मामले में सुप्रीम कोर्ट से फटकारनी नहीं लगी।' कंगना यहीं नहीं रुकीं। उन्होंने रामदेव को वरिष्ठ पर उपदेश देने से साफ मना किया और दो टुक कहा, ‘मुझे कैरेक्टर लेसन मत दीजिए। तुमसे तक बहुत ज्यादा बेहतर है मेरा कैरेक्टर।' नो फॉर्बिटवेंडर डिस्चै।’ यह पलटवार पतंजलि के ध्रामक विज्ञापनों से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के उस मामले की ओर इशारा था, जहां 2024 में रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ी थी।

कोर्ट के फैसले पर भड़के ओवैसी ने कहा- ‘हमारा धर्म, हम तय करेंगे’

बोले- जज तय नहीं कर सकते कि इस्लाम में क्या जरूरी है; फैसले को अनुच्छेद 19 और 25 के खिलाफ बताया

हैदराबाद, एजेंसी। स्कूलों में हिजाब या हेडस्कार्फ पहनने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कोर्ट के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि यह तय करना न्यायाधीशों का काम नहीं है कि इस्लाम में कौन-सी धार्मिक प्रथा जरूरी है और कौन-सी नहीं। ओवैसी ने इसे धर्म पर हमला बताते हुए कहा, ‘यह हमारा धर्म है और हम तय करेंगे कि क्या जरूरी है। जज कौन होते हैं यह तय करने वाले?’ सांसद ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले से ही धार्मिक प्रथाओं से जुड़े मामलों पर विचार कर रहा है। ऐसे में उनका कहना था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट को इस मुद्दे पर फैसला नहीं देना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट का आदेश सविधान्य का अनुच्छेद 19 और 25 के खिलाफ है। ओवैसी ने स्कूल छात्रा की हिजाब पहनने



की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि यह उसकी पसंद और निजता का मामला है। उन्होंने कहा, ‘वह हिजाब अपने सिर पर पहन रही है, न कि अपने दिमाग पर।’ उन्होंने दावा किया कि ऐसे फैसलों का मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा पर प्रतिकूल

प्रभाव पड़ सकता है। ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में मुस्लिम छात्राओं के स्कूल नामांकन को लेकर भी चिंता जताई और आरोप लगाया कि ऐसे कदम उनकी शिक्षा में बाधा डाल सकते हैं।

लोकसभा स्पीकर ने टीएमसी से 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

नई दिल्ली, एजेंसी। लोकसभा स्पीकर और सेक्रेटरी तुषमूल काग्रिस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में 20 बागी सांसदों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका दायर की थी। इस मामले में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उन सांसदों को नोटिस जारी कर सात दिन में जवाब मांगा है। यह घटनाक्रम तब हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को टीएमसी की अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला देने में हो रही देरी को चुनौती देने वाली अभिषेक बनर्जी की याचिका पर उन 20 सांसदों से जवाब मांगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमल्य बागची और वी मोहना की बेंच ने सांसदों को नोटिस जारी किया और स्पीकर के पास लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर जल्द विचार करने को कहा है।

लोकसभा स्पीकर और सेक्रेटरी जनरल की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत टीएमसी द्वारा दायर अयोग्यता याचिकाओं पर उन 20 सांसदों को पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इस दलील पर प्रतिक्रिया देते हुए जस्टिस जॉयमल्य बागची ने कहा कि सवाल नोटिस जारी करने का नहीं है, सवाल एक तय समय-सीमा के अंदर कार्यवाही पूरी करने का है। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि इन हथौड़ी जताई कि भारत की आधिकारिक नेशनलिटी सिटिजन्स पाटी आई इंडिया में शामिल हो गए। अभिषेक बनर्जी का तर्क है कि उनके इस आचरण के कारण संविधान के दलबदल-रोधी प्रावधानों के तहत उन्हें अयोग्य ठहराया जा सकता है।

पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी अमेरिका को की थी लीक

पूर्व सीडीएस अनिल चौहान का बड़ा खुलासा

नई दिल्ली, एजेंसी। पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) अनिल चौहान ने पिछले साल हुए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने आशंका जताई है कि इस ऑपरेशन से जुड़ी संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान की ओर से अमेरिका को लीक की गई होगी। पूर्व सीडीएस ने स्पष्ट किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम को लेकर पूरी तरह द्विपक्षीय बातचीत हुई थी और इसमें किसी भी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं थी। ऐसे में उन्होंने इस बात पर गहरी हैरानी जताई कि भारत की आधिकारिक घोषणा से पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इसका ऐलान कैसे कर दिया।

पूर्व सीडीएस ने बताया कि गत वर्ष 29 अप्रैल को आतंकवादी ठिकानों को सटीक निशाना बनाने का अहम फैसला लिया गया



था और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सेना पर किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक दबाव नहीं था। संघर्ष विराम की प्रक्रिया के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस (डीजीएमओ) के बीच आपसी सहमति से समय तय किया गया था। फोन पर

बातचीत के बाद शाम पांच बजे का समय निर्धारित हुआ था, जिससे यह पूरी तरह स्पष्ट है कि सीजफायर केवल दो सैन्य अधिकारियों के बीच की आपसी समझ का परिणाम था। जब उनसे यह सवाल किया गया कि यह गोपनीय जानकारी अमेरिका तक कैसे पहुंची, तो उन्होंने साफ

शब्दों में कहा कि यह सूचना भारतीय पक्ष की तरफ से बिल्कुल लीक नहीं की गई थी। उन्होंने अंदेशा जताया कि यह जानकारी निश्चित तौर पर दूसरे पक्ष यानी पाकिस्तान की तरफ से ही लीक हुई होगी। इसके अलावा, पूर्व सीडीएस ने किराना हिल्स पर किए गए हमलों की अटकलों पर भी विराम लगाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों वाले क्षेत्र किराना हिल्स को निशाना नहीं बनाया गया था। उन्होंने समझाया कि हमलों से पहले संग्रोथा क्षेत्र में कई ड्रोन भेजे गए थे, जिनका मुख्य उद्देश्य वहां के रडार का पता लगाना था। हवा में लंबे समय तक मंडराने के बाद यदि इन ड्रोनों को कोई लक्षित स्थान नहीं मिलता है, तो वे नीचे उतरकर टकरा जाते हैं। संभवतः इसी प्रक्रिया के दौरान कोई ड्रोन किराना हिल्सडियों से टकरा गया होगा, जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने गलत तरीके से प्रचारित किया था।

जनता ने जिस सीएम को नकारा है उन्हें वही पसंद है : पूनावाला

-शहजाद का अभिजीत दीपके पर पलटवार

नई दिल्ली, एजेंसी। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके द्वारा कुछ मुख्यमंत्रियों को देश के सर्वश्रेष्ठ नेताओं की सूची में शामिल करने पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे शहजाद पूनावाला ने अभिजीत दीपके और उनकी कॉंक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सीजेपी को फांड पार्टी करार देते हुए दीपके के चुने गए तीन मुख्यमंत्रियों के चयन पर गंभीर सवाल उठाए। हाल ही में एक कार्यक्रम में अभिजीत दीपके ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, द्रविड़ मुन्नेत्र कडगम (टीएमके) के नेता एमके स्टालिन और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनरारी विजयन को देश के सबसे अच्छे मुख्यमंत्रियों में शामिल किया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए शहजाद पूनावाला ने कहा, ये तीनों ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें



उनकी जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। तो सीजेपी को वो सीएम अच्छे लगते हैं, जिन्हें जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने तंज कसा कि कॉंक्रोच जनता पार्टी में से जनता को हटकर सिर्फ कॉंक्रोच पार्टी कर देना चाहिए, क्योंकि जनता का निर्णय कुछ और रहा है। पूनावाला ने अभिजीत दीपके के दावों का खंडन करते हुए तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था पर एमके स्टालिन के कार्यकाल को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि स्टालिन ने तमिलनाडु की नहीं, बल्कि अपने परिवार की अर्थव्यवस्था और अपने बेटे का उदय किया। आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि स्टालिन के पांच सालों के कार्यकाल में तमिलनाडु का कर्ज 2021 में 4.86 लाख करोड़ से बढ़कर 9.52

लाख करोड़ हो गया था। पूनावाला ने टिप्पणी की, जितना 60-70 सालों में बढ़ा, उतना पांच सालों में स्टालिन ने बढ़ाया। ये अच्छा कर रहे थे इकोनॉमी को। केरल के पूर्व सीएम पिनरारी विजयन के स्वास्थ्य मॉडल की तारीफ पर भी पूनावाला ने आपत्ति जताई। उन्होंने कोविड की दूसरी लहर का जिक्र करते हुए कहा कि केरल की आबादी साढ़े तीन करोड़ थी, और आंकड़ों के अनुसार वहां 71 हजार मौतें हुईं। इसकी तुलना में, उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ थी और वहां कोविड से जुड़ी मौतें 23 हजार 700 हुई थीं। पूनावाला ने इसे कुप्रबंधन बताते हुए कहा, छोटा राज्य होने के बावजूद केरल में यूपी से ज्यादा मौतें हुईं। ये था केरल हेल्थ मॉडल।

अन्नपूर्णा योजना पर ममता के सवाल, सुवंदु ने आंकड़ों के साथ दिया जवाब

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और विपक्ष के नेता सुवंदु अधिकारी के बीच जुबानी जंग एक बार फिर तेज हो गई है। इस बार विवाद की वजह अन्नपूर्णा योजना को लेकर उठे सवाल हैं। ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर योजना के लाभ को लेकर सवाल उठाए, जिसके बाद सुवंदु अधिकारी ने आंकड़े पेश करते हुए उनके आरोपों का जवाब दिया। दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी ने राज्य की राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है।

ममता बनर्जी ने सोमवार दोपहर सोशल मीडिया लाइव के दौरान अन्नपूर्णा योजना को लेकर कई सवाल उठाए। उन्होंने

दावा किया कि कुछ महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है और आरोप लगाया कि लाभार्थियों के चयन में जाति को आधार बनाया जा रहा है। उन्होंने ऐसे लोगों की जानकारी जुटाने की अपील की, जिन्हें कथित तौर पर योजना का लाभ नहीं मिला है। ममता ने कहा कि वह लोगों के साथ पहले भी खड़ी थीं और आगे भी रहेंगी।

सुवंदु ने बताए लाभार्थियों के आंकड़े ममता के आरोपों पर सुवंदु अधिकारी ने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि अन्नपूर्णा योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 45 लाख 64 हजार 472 लाभार्थियों को फायदा मिला है। उनके मुताबिक, इनमें करीब 19 लाख 20 हजार मुस्लिम लाभार्थी भी शामिल हैं। उन्होंने दावा

किया कि योजना का लाभ देते समय जाति और धर्म को आधार नहीं बनाया जाता।उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों की करीब एक लाख महिलाओं को योजना के तहत लाभ मिलने का भी दावा किया। नंदीग्राम के एक ब्लॉक का उदाहरण देते हुए अधिकारी ने कहा कि वहां दो हिंदू और 52 मुस्लिम परिवारों को आवास के लिए आर्थिक सहायता दी गई। उनके मुताबिक, सरकार का प्रयास है कि पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मिले। सुवंदु अधिकारी ने यह भी कहा कि अन्नपूर्णा योजना को लेकर सरकार के पास करीब 4.5 लाख शिकायतें पहुंची हैं। इनमें योजना का लाभ मिलने और लाभ से वंचित रहने, दोनों तरह की शिकायतें शामिल हैं। उन्होंने सवाल

उठाया कि यदि योजना का उद्देश्य सभी पात्र लोगों तक लाभ पहुंचाना था तो शुरूआत में इसे 25 से 60 वर्ष की आयु सीमा तक क्यों सीमित किया गया। उन्होंने बताया कि शिकायतों के समाधान के लिए एक पोर्टल भी शुरू किया गया है। आंकड़े गिनाने के बाद सुवंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के सोशल मीडिया लाइव को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ममता दोपहर में सोशल मीडिया पर ही रहती हैं और उन्हें सड़कों पर निकलने की जरूरत नहीं है।उन्होंने ममता की हालिया राजनीतिक गतिविधियों पर भी कटाक्ष किया और बाराईपुर तथा हलीशहर में उनके कार्यक्रमों का जिक्र करते हुए खेल के उदाहरण दिए।



संपादकीय

ज़हर बांटते उद्योग

कुछ उद्यमी मुगोफ़ की अंधी हवस में इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले कचरे को साफ़ किए बिना ही जलधाराओं में बहा देते हैं। जबकि उनकी नैतिक व कानूनी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी फैक्ट्रियों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ पर्यावरण व नदी-नालों को प्रदूषित न करें। हिमाचल प्रदेश स्थित बदी-नालागढ़ इलाके में कई औद्योगिक इकाइयां नदियों में जहरीले रसायन लगातार बहाती रही हैं। यह प्रदूषणकारक कचरा सिरसा नदी में बहा दिया जाता है, जो कालांतर सतलुज नदी में चला जाता है। यही वजह है कि आज सतलुज का प्रदूषित पानी जो चेतावनी दे रहा है उसे पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सरकारें भी नजरअंदाज नहीं कर सकती हैं। इसी आने वाले संकट के मद्देनजर ही बदी-नालागढ़ इलाके की अज्ञात औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जो मामले की गंभीरता को ही दर्शाता है। निस्संदेह, यह संकट कोई नई समस्या नहीं हैं। जो हमारे पर्यावरण संरक्षण से जुड़े नियम व कानूनों को लागू करने में तंत्र की बार-बार होने वाली विफलता को ही दर्शाता है। बदी-बरोटीवाला-नालागढ़ क्षेत्र से होने वाले औद्योगिक प्रदूषण के प्रामाणिक रिकॉर्ड कई सालों से मौजूद हैं। दरअसल, यह जहरीला कचरा इस औद्योगिक क्षेत्र से गुजरने वाली सिरसा नदी में डाल दिया जाता है। सिरसा नदी इन प्रदूषक तत्वों को आगे की ओर बहा ले जाती है। कालांतर यह सतलुज नदी में जाकर मिल जाता है। इस बाबत कई बार जांच भी की गई। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की कार्यवाही में बिना ट्रीट किए गए रसायनयुक्त कचरे व ठीक से ट्रीट न किए गए कचरे के बारे में उल्लेख किया गया है। ट्रिब्यूनल ने नियमों का पालन न करने वाली इकाइयों तथा ट्रीटमेंट सिस्टम की खामियों की ओर इशारा किया है। दरअसल, फार्मास्युटिकल प्रदूषण की समस्या बेहद गंभीर मामला है, क्योंकि पारंपरिक ढंग से ट्रीटमेंट करने वाले सिस्टम से सक्रिय फार्मास्युटिकल तत्व और एंटीबायोटिक के अवशेष पूरी तरह से नहीं हट पाते हैं। दरअसल, हाल के प्रकरण से एक और परेशान करने वाली विरोधीभासी बात सामने आई है। इस बाबत सूचना मिली थी कि रोपड़ हेडवर्क्स पर भारी मात्रा में जमा कचरे को नदी के बहाव की दिशा में बेफिक्री से छोड़ दिया गया। निस्संदेह, यदि यह कचरा नुकसानदायक था, तो इसे नदी में छोड़ने से समस्या महज एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित ही हुई है। कायदे से हेडवर्क्स में जमा कचरे की वैज्ञानिक तौर-तरीकों से निगरानी की जानी चाहिए थी। सही मायने में प्रदूषणकारक कचरे को ठिकाने लगाने से पहले उसके सैंपल लेकर उसकी जांच-पड़ताल की जानी जरूरी थी। निश्चित रूप से यह संकट बड़ा है और तत्काल इसका समाधान किया जाना चाहिए था। वास्तव में इस मामले को हिमाचल बनाम पंजाब के बीच आरोप-प्रत्यारोप का खेल नहीं बनने दिया जाना चाहिए। जरूरत इस बात की है कि दोनों सरकारें मिलकर प्रदूषण फैलाने वाले कचरे का वास्तविक स्रोत तलाशें क्योंकि अभी तक कचरे के असली स्रोत का पता नहीं चल सका है।

वितन-मन

कर्म के पाप-पुण्य में फंस जाता है जीव

ईश्वर क्षेत्रज्ञ या चेतन है, जैसा कि जीव भी है, लेकिन जीव केवल अपने शरीर के प्रति सचेत रहता है, जबकि भगवान समस्त शरीरों के प्रति सचेत रहते हैं। चूँकि वे प्रत्येक जीव के हृदय में वास करने वाले हैं, अतएव वे जीवविशेष की मानसिक गतिशीलता से परिचित रहते हैं। परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वर या नियंता के रूप में वास कर रहे हैं और जैसा जीव चाहता है वैसा करने के लिए जीव को निर्देशित करते रहते हैं। जीव भूल जाता है कि उसे क्या करना है। पहले तो वह किसी एक विधि से कर्म करने का संकल्प करता है, लेकिन फिर वह अपने ही कर्म के पाप-पुण्य में फंस जाता है। वह एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर ग्रहण करता है। चूँकि इस प्रकार वह आत्मा देहांतपरण कर जाता है, अत उसे अपने विगत (पूर्वकृत) कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ये कार्यकलाप तभी बदल सकते हैं जब जीव सतोगुण में स्थित हो और यह समझे कि उसे कौन से कर्म करने चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो उसके विगत कर्मों के सारे फल बदल जाते हैं। इसीलिए हमने यह कहा है कि पांच तत्वों- ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म में से चार शात हैं, कर्म शात नहीं है। परम चेतन ईश्वर जीव से इस मामले में समान हैं- भगवान तथा जीव दोनों की चेतनाएँ दिव्य हैं। यह चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न नहीं होती है। ऐसा सोचना भ्रांतिमूलक है। किंतु भगवान की चेतना भौतिकता से प्रभावित नहीं होती है। भगवान कहते हैं- जब वे इस भौतिक वि में अवतरित होते हैं तो उनकी चेतना पर भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वे इस तरह प्रभावित होते तो दिव्य विषयों के संबंध में उस तरह बोलने के अधिकारी न होते जैसा कि वे भगवद्गीता में बोलते हैं। भौतिक क्लमष-ग्रस्त चेतना से मुक्त हुए बिना कोई दिव्य-जगत के विषय में कुछ नहीं कह सकता। अतः भगवान भौतिक दृष्टि से कलुषित (दूषित) नहीं हैं। भगवद्गीता तो शिक्षा देती है कि हमें इस कलुषित चेतना को शुद्ध करना है।

आवश्यकता है

आवश्यकता है दैनिक सब का सपना समाचार पत्र को उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर व जिला स्तर पर संवाददाताओं की इच्छुक अभ्यर्थी संपर्क करें या व्हाट्सएप करें।

9456884327/8218179552



मनोज कुमार अग्रवाल

भारत में नशीले पदार्थों (ड्रग्स) की तस्करी देश की आंतरिक सुरक्षा, जन स्वास्थ्य और युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए एक अत्यंत गंभीर संकट बन चुकी है। भौगोलिक रूप से भारत दुनिया के दो सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्रों - पश्चिम में गोल्डन क्रैसेंट (अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान) और पूर्व में गोल्डन ट्रयंगल (म्यांमार, लाओस, थाईलैंड) के बीच स्थित है। इस संवेदनशील स्थिति के कारण देश में सीमा पार से बड़े पैमाने पर अवैध नशीले पदार्थों की आमद हो रही है। नशीले पदार्थों की तस्करी में भारत की भौगोलिक स्थिति भी खासा जिम्मेदार है पाकिस्तान, नेपाल और म्यांमार से सटी खुली और जटिल जमीनी सीमाएँ निगरानी के लिए एक बड़ी चुनौती है। तस्करीं द्वारा गुजरात और दक्षिणी राज्यों के विशाल तटीय क्षेत्रों का दुरुपयोग किया जा रहा है।अब नशे के सौदागर तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं डाकनेट क्रिप्टो करेंसी और सीमा पार से ड्रग्स गिराने के लिए ड्रोन का बढ़ता प्रयोग खतरा बढ़ा रहे हैं वहीं पारंपरिक अफीम-गांजे के स्थान पर हेरोइन, कोकीन और मेथामफेटामाइन जैसे घातक रसायनों सिंथेटिक ड्रग्स का बढ़ता चलन भी समस्या बन रहा है। आपकों बता दें कि देश में नशे और नशीले पदार्थों की तस्करी ने एक बार फिर केन्द्र और राज्यों की सरकारों को सस्ब्य किया है। नशीले पदार्थों की यह तस्करी का बड़ा हिस्सा पड़ोसी देश पाकिस्तान के माध्यम से सीमा

आतंकवाद के लिए खाद पानी है नशीले द्रव्यों की तस्करी!

पार से ड्रोनों के जरिये किया जाता है। नशे को लेकर किये गये एक व्यापक सर्वेक्षण के अनुसार पाकिस्तान एक प्रकार से नशीले पदार्थों के भण्डारण का केन्द्र बन गया है जहां से इन पदार्थों का बहुत बड़ा भाग भारत के पंजाब प्रांत में ड्रोनों के जरिये खपाया जाता है। भारत से फिर यह सामान तस्करी के जरिये कई अन्य देशों में भेजा जाता है जहां इसकी बड़ी मांग होती है। पाकिस्तान से भारत में पंजाब सीमा के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी यूं तो दशकों पूर्व से की जाती आ रही है। कभी नावों के माध्यम से, कभी सुरंगों के जरिये पाकिस्तानी पंजाब के सीमा-पार से भारतीय पंजाब में अफीम और हेरोइन की तस्करी की जाती रही है। तथापि, आजकल नावों का कार्य ड्रोनों से लिया जाने लगा है। ड्रोनों के जरिये पाकिस्तानी सीमा-पार से भारतीय पंजाब में अफीम, हेरोइन के साथ हथियारों की खपत भेजना जैसे आम बात हो गई है वैसे तो नशे के लिए अफीम, चरस, कोकीन आदि अनेकानेक द्रव्यों एवं पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है किन्तु वर्तमान में हेरोइन सर्वोत्तम नशीला पदार्थ बन गया है। हाल ही में एक और बड़ा खतरनाक नशीला पदार्थ आईस भी बड़ी चर्चा में आया है। विगत कई वर्षों से हेरोइन की तस्करी और इसके सेवन की मात्रा में निरन्तर वृद्धि हुई है। इसका बड़ा प्रमाण इस एक तथ्य से मिल जाता है कि इन दिनों सीमाओं पर विशेष सुरक्षा चौकसी होने के बावजूद तस्करी से बरामद होने वाली खेपों की संख्या और मात्रा बढ़ गई है। इसके लिए तस्करीं द्वारा अत्याधुनिक तकनीकों का भी उपयोग किया जाने लगा है। सीमा सुरक्षा बलों की निरन्तर चौकसी और सतर्कता के बावजूद ऐसी घटनाएँ धमने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले पांच वर्षों में पंजाब सीमा पर ड्रोन तस्करी की घटनाएँ बढ़ कर तीन से 304 प्रति वर्ष तक हो गई हैं। नशीले पदार्थों की तस्करी के संबंध में स्थितियों की गम्भीरता को पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा की गई इस एक कठोर टिप्पणी से बेहतर समझा जा सकता है कि नशे का यह सम्पूर्ण कारोबार महज एक आसराधिक कार्य मात्र नहीं रह गया, अपितु राष्ट्र और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन गया है।

यूपीआई@10: भुगतान की दुनिया में भारत का नया अध्याय

बिल चुकाने, ऑनलाइन खरीदारी, मोबाइल रिचार्ज, निजली-पानी-गैस जैसे उपयोगिता बिलों के भुगतान, रेल-बस-विमान टिकट बुकिंग, स्कूल-कॉलेज की फीस, अस्पतालों में भुगतान तथा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को तुरंत पैसे भजने के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा छोटे व्यापारियों से लेकर बड़े कारोबारी प्रतिष्ठानों तक डिजिटल लेन-देन में यूपीआई का व्यापक इस्तेमाल हो रहा है। यानी आज यूपीआई भारत के दैनिक जीवन में नकद भुगतान के एक आसान, तेज और सुविधाजनक डिजिटल विकल्प के रूप में स्थापित हो चुका है। बहरहाल, यहां पाठकों को यह भी बताता चलूं कि अन्य देशों की तुलना में भारत का यूपीआई डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में असाधारण पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2026 में यूपीआई दुनिया के लगभग 49% रियल-टाइम भुगतान लेन-देन को संचाल रहा है, यानी दुनिया में होने वाले लगभग हर दो तत्काल डिजिटल भुगतानों में एक यूपीआई के माध्यम से होता है। भारत में इसकी मात्रा भी तेजी से बढ़ी है और वित्त वर्ष 2025-26 में यूपीआई पर करीब 24,162 करोड़ लेन-देन हुए। मई 2026 में अकेले यूपीआई ने 23,201.93 मिलियन यानी लगभग 2,320 करोड़ लेन-देन किए, जिनका कुल मूल्य करीब रू.29.90 लाख करोड़ रहा। इस तुलना में भारत की खासियत यह है कि यूपीआई केवल बड़े शहरों या बड़े कारोबार तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे दुकानदार, रेहड़ी-पटरी वाले, ग्रामीण उपभोक्ता और आम नागरिक तक इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यूपीआई अब 11 देशों में उपलब्ध है और वैश्विक स्तर पर भारत की डिजिटल भुगतान व्यवस्था का एक प्रमुख उदाहरण बन चुका है। अन्य शब्दों में कहें तो

वर्ष 2016 में शुरू हुई यह व्यवस्था आज देश के कोने-कोने तक पहुंच चुकी है। पहले जहां डिजिटल भुगतान सीमित था, वहीं अब चायवाले, सब्जीवाले, छोटे दुकानदार और आम लोग भी आसानी से यूपीआई से पैसे ले-दे रहे हैं। एक दशक में यूपीआई लेन-देन में हुई भारी वृद्धि इसकी लोकप्रियता और लोगों के भरोसे को दिखाती है।यूपीआई से बैंकिंग आसान, तेज और सुविधाजनक हुई है। लोगों को नकदी निकालने के लिए बैंक जाने या लंबी कतार में खड़े होने की जरूरत कम हुई है। आज पलभर में ही दूर बैठे व्यक्ति को तुरंत पैसे भेजे जा सकते हैं। इतना ही नहीं, नकदी कम रखने से चोरी और लूट का जोखिम भी घटा है। डिजिटल भुगतान से लेन-देन में पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाने में मदद मिली है।यूपीआई की सफलता के पीछे डिजिटल इंडिया अभियान और इंटरनेट कनेक्टिविटी का विस्तार भी महत्वपूर्ण रहा है। देश में मोबाइल और ब्रॉडबैंड की पहुंच बढ़ने से डिजिटल भुगतान आम लोगों की रोजगारी की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। यही कारण है कि दूसरे देश भी यूपीआई जैसी भारतीय डिजिटल भुगतान व्यवस्था में रुचि दिखा रहे हैं।हालाँकि, अभी कुछ चुनौतियां बाकी हैं। बैंक का सर्वर डाउन होना, अधिक ट्रैफिक के कारण भुगतान अटकना और गलती से गलत व्यक्ति को पैसे भेज देना जैसी समस्याएं लोगों के लिए परेशानी पैदा करती हैं। इन समस्याओं का स्थायी समाधान जरूरी है। कुल मिलाकर, यूपीआई केवल पैसे भेजने और लेने का माध्यम नहीं, बल्कि भारत की डिजिटल प्रगति और आत्मनिर्भर तकनीकी क्षमता का प्रतीक बन चुका है। दस साल की इसकी यात्रा बताती है कि जब तकनीक को आम आदमी की जरूरतों से जोड़ा जाता है, तो

शिक्षित राष्ट्र के बिना विश्व गुरु की अवधारणा बेमानी



दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार के दौरान अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रम्प ने 25 फरवरी 2020 को नई दिल्ली के मोतीबाग स्थित सर्वोदय सह-शिक्षा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का दौरा किया था। दिल्ली के सारकारी स्कूलों और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को देखने के लिए कई अन्य विदेशी मेहमान और प्रतिनिधिमंडल भी आ चुके हैं। समय-समय पर विभिन्न देशों के शिक्षाविद, राजनयिक और प्रतिनिधिमंडल दिल्ली के सरकारी स्कूलों की बुनियादी संरचना, कक्षाओं और शैक्षणिक गतिविधियों का निरीक्षण करने दिल्ली आते रहे हैं। क्या इसी तरह के आधुनिक सरकारी स्कूल पूरे देश में संचालित नहीं हो सकते? क्या वजह है कि देश के अधिकांश राज्यों में अनेकानेक सरकारी स्कूल भवन जर्जर हैं ? कहीं स्कूल में भैंसों के तबले हैं तो कहीं पेड़ के नीचे व खुले आसमान तले क्लास लगाई जा रही है। कहीं क्लासरूम नहीं। कहीं अध्यापक नहीं तो कहीं बिजली व पीने का पानी नहीं तो कहीं शौचालय नहीं। कहीं बच्चे रोज नदी पार कर स्कूल आते

जाते हैं तो कहीं कीचड़ और दलदल भरी गड्ढादर सड़कों से गुजर कर स्कूल आना होता है। यदि देश की सरकारें शिक्षा के प्रति गंभीर होतीं और उनका भारत को विश्वगुरु बनाने का दिंडोरा महज ढोल पीटना न होता तो आज सुप्रिय कोर्ट के जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले को महाराष्ट्र में शिक्षा पर घटते बजट और सरकारी मराठी माध्यम के स्कूलों के बंद होने पर गहरी चिंता जताते हुये यह न कहना पड़ता कि नासिक कुंभ मेले के लिए लगभग रु.32,000 करोड़ का भारी-भरकम बजट तय किया गया है। अगर इस राशि का मात्र 0.1% यानी लगभग रू.32 करोड़ भी शिक्षा पर खर्च किया जाता, तो राज्य के 100 से 125 बंद हो रहे मराठी स्कूलों को बचाया जा सकता था। अखिर जस्टिस प्रसन्ना को क्यों कहना पड़ा कि देश में छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन शिक्षा का बजट बढ़ने के बजाय घट रहा है, जो पिछले कई वर्षों से 13% के आंकड़े को भी नहीं छू सका है। उन्होंने गढ़चिरोली की एक घटना का उदाहरण भी दिया जहां

तस्करी के गिरेबान तक पहुंचने भी तो चाहिए। कुछ भी हो अथवा कुछ भी किया जाए, देश को नशीले पदार्थों की तस्करी की इस लानत से मुक्ति मिलनी चाहिए। देश की कामकाजी आबादी खासकर युवा और कालेज छात्र छात्राएं स्कूली बच्चे इसकी चपेट में आकर मानसिक और शारीरिक रूप से पंगु हो रहे हैं।नारको-टेरिज्म जड़ जमा रहा है। ड्रग्स की तस्करी से होने वाली अवैध कमाई का इस्तेमाल सीधे तौर पर भारत विरोधी आतंकवादी गतिविधियों और उग्रवाद की फंडिंग में किया जाता है। नशे की दैनिक तलब पूरी करने के लिए युवा चोरी, लूटपाट और संगठित अपराधों के रास्ते पर जा रहे हैं। अवैध काले धन और हवाला कारोबार के कारण देश की मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचता है। ऐसा नहीं है कि सरकार को नशीले द्रव्यों की तस्करी और उसके कारण हो रही बबादी का भान नहीं है सरकार ने इस ओर नियंत्रण के लिए की प्रभावी कदम उठाए हैं। खुद प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रीय संबोधन में नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने और नशे के दुष्परिणामों से युवाओं को आगाह किया है। भारत सरकार ने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है. गृह मंत्रालय ने अगले 3 वर्षों में देश को पूरी तरह ड्रग-मुक्त बनाने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 2026 – 2029 जारी किया है।हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यूएई से ₹1,000 करोड़ के अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट के मास्टरमाइंड वीरेंद्र सिंह बसोया का सफलतापूर्वक प्रत्यर्पण कराया गया है।डिजिटल कवच बनाया गया है नागरिकों की मदद के लिए राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन 1933 मानस शुरू की गई है, जिस पर लोग सीधे तौर पर भारत विरोधी पदार्थों की तस्करी रोकने और नशे के दुष्परिणामों से युवाओं को आगाह किया है। भारत सरकार ने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है. गृह मंत्रालय ने अगले 3 वर्षों में देश को पूरी तरह ड्रग-मुक्त बनाने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 2026 – 2029 जारी किया है।हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यूएई से ₹1,000 करोड़ के अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट के मास्टरमाइंड वीरेंद्र सिंह बसोया का सफलतापूर्वक प्रत्यर्पण कराया गया है।डिजिटल कवच बनाया गया है नागरिकों की मदद के लिए राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन 1933 मानस शुरू की गई है, जिस पर लोग सीधे तौर पर भारत विरोधी पदार्थों की तस्करी रोकने और नशे के दुष्परिणामों से युवाओं को आगाह किया है। भारत सरकार ने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है. गृह मंत्रालय ने अगले 3 वर्षों में देश को पूरी तरह ड्रग-मुक्त बनाने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 2026 – 2029 जारी किया है।हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यूएई से ₹1,000 करोड़ के अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट के मास्टरमाइंड वीरेंद्र सिंह बसोया का सफलतापूर्वक प्रत्यर्पण कराया गया है।डिजिटल कवच बनाया गया है नागरिकों की मदद के लिए राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन 1933 मानस शुरू की गई है, जिस पर लोग सीधे तौर पर भारत विरोधी पदार्थों की तस्करी रोकने और नशे के दुष्परिणामों से युवाओं को आगाह किया है। भारत सरकार ने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है. गृह मंत्रालय ने अगले 3 वर्षों में देश को पूरी तरह ड्रग-मुक्त बनाने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 2026 – 2029 जारी किया है।हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यूएई से ₹1,000 करोड़ के अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट के मास्टरमाइंड वीरेंद्र सिंह बसोया का सफलतापूर्वक प्रत्यर्पण कराया गया है।डिजिटल कवच बनाया गया है नागरिकों की मदद के लिए राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन 1933 मानस शुरू की गई है, जिस पर लोग सीधे तौर पर भारत विरोधी पदार्थों की तस्करी रोकने और नशे के दुष्परिणामों से युवाओं को आगाह किया है। भारत सरकार ने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है. गृह मंत्रालय ने अगले 3 वर्षों में देश को पूरी तरह ड्रग-मुक्त बनाने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 2026 – 2029 जारी किया है।हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यूएई से ₹1,000 करोड़ के अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट के मास्टरमाइंड वीरेंद्र सिंह बसोया का सफलतापूर्वक प्रत्यर्पण कराया गया है।डिजिटल कवच बनाया गया है नागरिकों की मदद के लिए राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन 1933 मानस शुरू की गई है, जिस पर लोग सीधे तौर पर भारत विरोधी पदार्थों की तस्करी रोकने और नशे के दुष्परिणामों से युवाओं को आगाह किया है। भारत सरकार ने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है. गृह मंत्रालय ने अगले 3 वर्षों में देश को पूरी तरह ड्रग-मुक्त बनाने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 2026 – 2029 जारी किया है।हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यूएई से ₹1,000 करोड़ के अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट के मास्टरमाइंड वीरेंद्र सिंह बसोया का सफलतापूर्वक प्रत्यर्पण कराया गया है।डिजिटल कवच बनाया गया है नागरिकों की मदद के लिए राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन 1933 मानस शुरू की गई है, जिस पर लोग सीधे तौर पर भारत विरोधी पदार्थों की तस्करी रोकने और नशे के दुष्परिणामों से युवाओं को आगाह किया है। भारत सरकार ने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है. गृह मंत्रालय ने अगले 3 वर्षों में देश को पूरी तरह ड्रग-मुक्त बनाने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 2026 – 2029 जारी किया है।हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यूएई से ₹1,000 करोड़ के अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट के मास्टरमाइंड वीरेंद्र सिंह बसोया का सफलतापूर्वक प्रत्यर्पण कराया गया है।डिजिटल कवच बनाया गया है नागरिकों की मदद के लिए राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन 1933 मानस शुरू की गई है, जिस पर लोग सीधे तौर पर भारत विरोधी पदार्थों की तस्करी रोकने और नशे के दुष्परिणामों से युवाओं को आगाह किया है। भारत सरकार ने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है. गृह मंत्रालय ने अगले 3 वर्षों में देश को पूरी तरह ड्रग-मुक्त बनाने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 2026 – 2029 जारी किया है।हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यूएई से ₹1,000 करोड़ के अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट के मास्टरमाइंड वीरेंद्र सिंह बसोया का सफलतापूर्वक प्रत्यर्पण कराया गया है।डिजिटल कवच बनाया गया है नागरिकों की मदद के लिए राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन 1933 मानस शुरू की गई है, जिस पर लोग सीधे तौर पर भारत विरोधी पदार्थों की तस्करी रोकने और नशे के दुष्परिणामों से युवाओं को आगाह किया है। भारत सरकार ने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है. गृह मंत्रालय ने अगले 3 वर्षों में देश को पूरी तरह ड्रग-मुक्त बनाने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 2026 – 2029 जारी किया है।हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यूएई से ₹1,000 करोड़ के अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट के मास्टरमाइंड वीरेंद्र सिंह बसोया का सफलतापूर्वक प्रत्यर्पण कराया गया है।डिजिटल कवच बनाया गया है नागरिकों की मदद के लिए राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन 1933 मानस शुरू की गई है, जिस पर लोग सीधे तौर पर भारत विरोधी पदार्थों की तस्करी रोकने और नशे के दुष्परिणामों से युवाओं को आगाह किया है। भारत सरकार ने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है. गृह मंत्रालय ने अगले 3 वर्षों में देश को पूरी तरह ड्रग-मुक्त बनाने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 2026 – 2029 जारी किया है।हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यूएई से ₹1,000 करोड़ के अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट के मास्टरमाइंड वीरेंद्र सिंह बसोया का सफलतापूर्वक प्रत्यर्पण कराया गया है।डिजिटल कवच बनाया गया है नागरिकों की मदद के लिए राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन 1933 मानस शुरू की गई है, जिस पर लोग सीधे तौर पर भारत विरोधी पदार्थों की तस्करी रोकने और नशे के दुष्परिणामों से युवाओं को आगाह किया है। भारत सरकार ने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है. गृह मंत्रालय ने अगले 3 वर्षों में देश को पूरी तरह ड्रग-मुक्त बनाने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 2026 – 2029 जारी किया है।हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यूएई से ₹1,000 करोड़ के अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट के मास्टरमाइंड वीरेंद्र सिंह बसोया का सफलतापूर्वक प्रत्यर्पण कराया गया है।डिजिटल कवच बनाया गया है नागरिकों की मदद के लिए राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन 1933 मानस शुरू की गई है, जिस पर लोग सीधे तौर पर भारत विरोधी पदार्थों की तस्करी रोकने और नशे के दुष्परिणामों से युवाओं को आगाह किया है। भारत सरकार ने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है. गृह मंत्रालय ने अगले 3 वर्षों में देश को पूरी तरह ड्रग-मुक्त बनाने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 2026 – 2029 जारी किया है।हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यूएई से ₹1,000 करोड़ के अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट के मास्टरमाइंड वीरेंद्र सिंह बसोया का सफलतापूर्वक प्रत्यर्पण कराया गया है।डिजिटल कवच बनाया गया है नागरिकों की मदद के लिए राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन 1933 मानस शुरू की गई है, जिस पर लोग सीधे तौर पर भारत विरोधी पदार्थों की तस्करी रोकने और नशे के दुष्परिणामों से युवाओं को आगाह किया है। भारत सरकार ने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है. गृह मंत्रालय ने अगले 3 वर्षों में देश को पूरी तरह ड्रग-मुक्त बनाने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 2026 – 2029 जारी किया है।हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यूएई से ₹1,000 करोड़ के अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट के मास्टरमाइंड वीरेंद्र सिंह बसोया का सफलतापूर्वक प्रत्यर्पण कराया गया है।डिजिटल कवच बनाया गया है नागरिकों की मदद के लिए राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन 1933 मानस शुरू की गई है, जिस पर लोग सीधे तौर पर भारत विरोधी पदार्थों की तस्करी रोकने और नशे के दुष्परिणामों से युवाओं को आगाह किया है। भारत सरकार ने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है. गृह मंत्रालय ने अगले 3 वर्षों में देश को पूरी तरह ड्रग-मुक्त बनाने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 2026 – 2029 जारी किया है।हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यूएई से ₹1,000 करोड़ के अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट के मास्टरमाइंड वीरेंद्र सिंह बसोया का सफलतापूर्वक प्रत्यर्पण कराया गया है।डिजिटल कवच बनाया गया है नागरिकों की मदद के लिए राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन 1933 मानस शुरू की गई है, जिस पर लोग सीधे तौर पर भारत विरोधी पदार्थों की तस्करी रोकने और नशे के दुष्परिणामों से युवाओं को आगाह किया है। भारत सरकार ने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है. गृह मंत्रालय ने अगले 3 वर्षों में देश को पूरी तरह ड्रग-मुक्त बनाने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 2026 – 2029 जारी किया है।हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यूएई से ₹1,000 करोड़ के अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट के मास्टरमाइंड वीरेंद्र सिंह बसोया का सफलतापूर्वक प्रत्यर्पण कराया गया है।डिजिटल कवच बनाया गया है नागरिकों की मदद के लिए राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन 1933 मानस शुरू की गई है, जिस पर लोग सीधे तौर पर भारत विरोधी पदार्थों की तस्करी रोकने और नशे के दुष्परिणामों से युवाओं को आगाह किया है। भारत सरकार ने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है. गृह मंत्रालय ने अगले 3 वर्षों में देश को पूरी तरह ड्रग-मुक्त बनाने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 2026 – 2029 जारी किया है।हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यूएई से ₹1,000 करोड़ के अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट के मास्टरमाइंड वीरेंद्र सिंह बसोया का सफलतापूर्वक प्रत्यर्पण कराया गया है।डिजिटल कवच बनाया गया है नागरिकों की मदद के लिए राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन 1933 मानस शुरू की गई है, जिस पर लोग सीधे तौर पर भारत विरोधी पदार्थों की तस्करी रोकने और नशे के दुष्परिणामों से युवाओं को आगाह किया है। भारत सरकार ने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है. गृह मंत्रालय ने अगले 3 वर्षों में देश को पूरी तरह ड्रग-मुक्त बनाने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 2026 – 2029 जारी किया है।हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यूएई से ₹1,000 करोड़ के अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट के मास्टरमाइंड वीरेंद्र सिंह बसोया का सफलतापूर्वक प्रत्यर्पण कराया गया है।डिजिटल कवच बनाया गया है नागरिकों की मदद के लिए राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन 1933 मानस शुरू की गई है, जिस पर लोग सीधे तौर पर भारत विरोधी पदार्थों की तस्करी रोकने और नशे के दुष्परिणामों से युवाओं को आगाह किया है। भारत सरकार ने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है. गृह मंत्रालय ने अगले 3 वर्षों में देश को पूरी तरह ड्रग-मुक्त बनाने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 2026 – 2029 जारी किया है।हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यूएई से ₹1,000 करोड़ के अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट के मास्टरमाइंड वीरेंद्र सिंह बसोया का सफलतापूर्वक प्रत्यर्पण कराया गया है।डिजिटल कवच बनाया गया है नागरिकों की मदद के लिए राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन 1933 मानस शुरू की गई है, जिस पर लोग सीधे तौर पर भारत विरोधी पदार्थों की तस्करी रोकने और नशे के दुष्परिणामों से युवाओं को आगाह किया है। भारत सरकार ने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है. गृह मंत्रालय ने अगले 3 वर्षों में देश को पूरी तरह ड्रग-मुक्त बनाने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 2026 – 2029 जारी किया है।हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यूएई से ₹1,000 करोड़ के अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट के मास्टरमाइंड वीरेंद्र सिंह बसोया का सफलतापूर्वक प्रत्यर्पण कराया गया है।डिजिटल कवच बनाया गया है नागरिकों की मदद के लिए राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन 1933 मानस शुरू की गई है, जिस पर लोग सीधे तौर पर भारत विरोधी पदार्थों की तस्करी रोकने और नशे के दुष्परिणामों से युवाओं को आगाह किया है। भारत सरकार ने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है. गृह मंत्रालय ने अगले 3 वर्षों में देश को पूरी तरह ड्रग-मुक्त बनाने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 2026 – 2029 जारी किया है।हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यूएई से ₹1,000 करोड़ के अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट के मास्टरमाइंड वीरेंद्र सिंह बसोया का सफलतापूर्वक प्रत्यर्पण कराया गया है।डिजिटल कवच बनाया गया है नागरिकों की मदद के लिए राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन 1933 मानस शुरू की गई है, जिस पर लोग सीधे तौर पर भारत विरोधी पदार्थों की तस्करी रोकने और नशे के दुष्परिणामों से युवाओं को आगाह किया है। भारत सरकार ने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है. गृह मंत्रालय ने अगले 3 वर्षों में देश को पूरी तरह ड्रग-मुक्त बनाने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 2026 – 2029 जारी किया है।हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यूएई से ₹1,000 करोड़ के अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट के मास्टरमाइंड वीरेंद्र सिंह बसोया का सफलतापूर्वक प्रत्यर्पण कराया गया है।डिजिटल कवच बनाया गया है नागरिकों की मदद के लिए राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन 1933 मानस शुरू की गई है, जिस पर लोग सीधे तौर पर भारत विरोधी पदार्थों की तस्करी रोकने और नशे के दुष्परिणामों से युवाओं को आगाह किया है। भारत सरकार ने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है. गृह मंत्रालय ने अगले 3 वर्षों में देश को पूरी तरह ड्रग-मुक्त बनाने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 2026 – 2029 जारी किया है।हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यूएई से ₹1,000 करोड़ के अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट के मास्टरमाइंड वीरेंद्र सिंह बसोया का सफलतापूर्वक प्रत्यर्पण कराया गया है।डिजिटल कवच बनाया गया है नागरिकों की मदद के लिए राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन 1933 मानस शुरू की गई है, जिस पर लोग सीधे तौर पर भारत विरोधी पदार्थों की तस्करी रोकने और नशे के दुष्परिणामों से युवाओं को आगाह किया है। भारत सरकार ने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है. गृह मंत्रालय ने अगले 3 वर्षों में देश को पूरी तरह ड्रग-मुक्त बनाने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 2026 – 2029 जारी किया है।हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यूएई से ₹1,000 करोड़ के अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट के मास्टरमाइंड वीरेंद्र सिंह बसोया का सफलतापूर्वक प्रत्यर्पण कराया गया है।डिजिटल कवच बनाया गया है नागरिकों की मदद के लिए राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन 1933 मानस शुरू की गई है, जिस पर लोग सीधे तौर पर भारत विरोधी पदार्थों की तस्करी रोकने और नशे के दुष्परिणामों से युवाओं को आगाह किया है। भारत सरकार ने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है. गृह मंत्रालय ने अगले 3 वर्षों में देश को पूरी तरह ड्रग-मुक्त बनाने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 20

रजबपुर थाना पुलिस ने एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार

अमरोहा (सब का सपना):- जनपद में रजबपुर थाना पुलिस ने 26 अगस्त को एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त की पहचान राहुल (31 वर्ष) पुत्र डालचंद निवासी ग्राम अहमदपुर देवीपुरा, रजबपुर थाना, जनपद अमरोहा के रूप में हुई है। उसे भारतीय न्याय संहिता (बीएनएसएस) की धारा 170, 126 और 135 के तहत



गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय अमरोहा भेजा गया। यह कार्रवाई

अमरोहा पुलिस एसपी लखन सिंह यादव जी के निर्देशानुसार, अमरोहा पुलिस एडिशनल एसपी अपर पुलिस अखिलेश भदौरिया, क्षेत्राधिकारी डॉ. प्रदीप कुमार सिंह और थानाध्यक्ष विकास सहरावत के पर्यवेक्षण में की गई। अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली टीम में उपनिरीक्षक लोकेश कुमार, हेड कांस्टेबल देवेन्द्र सिंह और कांस्टेबल योगेश कुमार शामिल थे। सभी रजबपुर थाना में तैनात हैं।

तीसरी मादा गुलदार वन विभाग के पिंजरे में कैद क्षेत्र दहशत का माहौल

नगीना/बिजनौर (सब का सपना):- मादा गुलदारों के पकड़े जाने का सिलसिला रूकने का नाम नहीं ले रहा है, क्षेत्र के ग्राम कादीपुर में वन विभाग द्वारा लगाये गये पिंजरे में एक और मादा गुलदार कैद हो गई। मादा गुलदार की उम्र लगभग 5 वर्ष बताई जा रही है। पिंजरे में कैद गुलदार को पिंजरे सहित अग्रिम आदेश तक कृषि फार्म में रखा गया है। क्षेत्रीय वन दरोगा धर्मेन्द्र कुमार ने बताया कि नगीना रेंज के ग्राम कादीपुर में ग्रामीणों की मांग पर गुलदार को पकड़ने के लिए भानु प्रताप सिंह के भेट्टे के पास दिनांक 9 अगस्त को पिंजरा लगाया था,



गुलदार के चारे के लिए पिंजरे में चार मुर्गी रखी थी, मंगलवार / बुधवार की रात्रि में किसी समय एक मादा गुलदार उम्र लगभग 5 वर्ष पिंजरे में कैद हो गई। बुधवार की सुबह सूचना पर क्षेत्रीय वन क्षेत्र अधिकारी प्रदीप

विज्ञान केंद्र पहुंचाया। दर्जना उसे सुरक्षित विज्ञान केंद्र में रखा गया है। जिसकी सूचना वन विभाग के उच्चाधिकारियों को दे दी गई है जो भी निर्देश होंगे उसी पर कार्यवाही की जाएगी। उधर ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्रों में गुलदार देखे जाने की जानकारी वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को समय समय पर देते रहे रहे हैं लेकिन एक भी अधिकारी कर्मचारी ने वहां आकर जानकारी लेना भी मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने जिलाधिकारी से गुलदार पकड़ने के लिए और पिंजरे लगाए जाने के मांग की है।

अहिल्याबाई होल्कर मातृशक्ति योजना पर धनगर समाज ने जताया आभार

बिजनौर (सब का सपना):- पुण्य श्लोक लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर के नाम पर शुरू की गई मातृशक्ति योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु की बुजुर्ग महिलाओं को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दिए जाने पर धनगर समाज ने प्रदेश की भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। बुधवार को भाजपा युवा मोर्चा के जिला कार्यकारिणी सदस्य योगेंद्र पाल योगी के नेतृत्व में धनगर समाज के युवा रामलीला चौराहा स्थित पुण्य श्लोक लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर की प्रतिमा पर एकत्र हुए। इस दौरान उन्होंने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर



प्रदेश सरकार की इस पहल की सराहना की। योगेंद्र पाल योगी ने कहा कि भाजपा सरकार महापुरुषों के सम्मान के साथ-साथ समाज के विभिन्न वर्गों के हित में योजनाएं संचालित कर रही है। लोकमाता

महिलाएं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बुजुर्ग महिलाओं के लिए शुरू की गई यह योजना नारी सम्मान और मातृशक्ति के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस अवसर पर रामगोपाल धनगर, एसपी सिंह धनगर, अतुल पाल धनगर, अमित पाल, रामसिंह पाल, वरिष्ठ भाजपा नेता विकास अग्रवाल, जयवीर पाल सोनू, दीपक पाल धनगर, अक्षय हनी, युवराज पाल एडवोकेट, ओम प्रकाश पाल, राजकुमार पाल, हेमेंद्र पाल, मुकेश पाल और देवेन्द्र पाल चीनू सहित धनगर समाज के लोग मौजूद रहे।

धामपुर में शानो-शौकत से निकला जशने ईद मिलादुन्नबी का जुलूस

धामपुर/बिजनौर (सब का सपना):- जशने ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर बुधवार को अंजुमन फलाह अहले सुन्नत कमेटी के तत्वावधान में नगर में जुलूस-ए-मुहम्मदी शानो-शौकत के साथ निकाला गया। जुलूस का शुभारंभ मोहल्ला बंदूकचियां स्थित मदरसा नूरिया से शहर इमाम मुफ्ती जाकिर हुसैन ने हरी झंडी दिखाकर किया। जुलूस में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए। लोग



सरकार की आमद मरहबा के नारे लगाते हुए आगे बढ़े। जुलूस नगर

समापन किया गया। जुलूस के दौरान नगर के विभिन्न स्थानों पर लोगों ने पुष्प वर्षा व स्वागत कर आपसी भाईचारे का संदेश दिया। इस दौरान हिंदू, मुस्लिम और सिख समाज के लोगों ने आपसी सौहार्द और गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करते हुए जुलूस में शामिल लोगों को सौफ, मिठाई और फल वितरित किए। जुलूस को लेकर पुलिस-प्रशासन की ओर से मार्गों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे।

रक्षाबंधन को लेकर बाजारों में बढ़ी रौनक, राखियों की खरीदारी में जुटी बहनें



नगीना/बिजनौर (सब का सपना):- भाई-बहन के पवित्र प्रेम और अटूट रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व नजदीक आते ही नगर के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए रंग-बिरंगी, आकर्षक और मनमोहक राखियों की खरीदारी शुरू कर दी है।

रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त को मनाया जाएगा। रक्षाबंधन को लेकर नगर के मुख्य बाजारों में जगह-जगह राखियों के स्टॉल सज गए हैं। इन स्टॉलों पर विभिन्न डिजाइन और आकर्षक रंगों की राखियां महिलाओं एवं युवतियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। बहनें अपने भाइयों



की खरीदारी के चलते बाजारों में दिनभर चहल-पहल बनी हुई है। रक्षाबंधन को लेकर मिठाई विक्रेताओं ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। दुकानों पर विभिन्न प्रकार की मिठाइयां तैयार की जा रही हैं। पर्व नजदीक आने के साथ ही बाजारों में खरीदारी और बढ़ने की उम्मीद है।

अमरोहा जनपद में गंगा का जलस्तर 10cm घटा तिगरी में 200.50 मीटर पहुंचा खेतों और गंगा घाट पर अब भी पानी



अमरोहा (सब का सपना):- जनपद में गंगा नदी का जलस्तर लगातार घट-बढ़ रहा है। बुधवार को तिगरी में गंगा का जलस्तर 200.50 मीटर दर्ज किया गया। मंगलवार को यह 200.60 मीटर था। पानी 24 घंटे में जलस्तर 10 सेंटीमीटर कम हुआ है। हालांकि इसी दौरान बिजनौर बैराज से 67,904 क्यूसेक पानी गंगा में छोड़ा गया। बाढ़ खंड विभाग

के जेई सुभाष चंद गहलौत ने बताया कि बिजनौर बैराज से पानी छोड़े जाने के बावजूद तिगरी में गंगा का जलस्तर फिलहाल कम हुआ है। विभाग की ओर से जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। गंगा का जलस्तर घटने के बाद भी खादर क्षेत्र के खेतों में पानी भरा हुआ है। इससे किसानों और ग्रामीणों की परेशानी बनी हुई है। खेतों में पानी



जमा होने के कारण पशुओं के लिए चारा लाने में भी ग्रामीणों को दिक्कत हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि जलभराव के कारण खेतों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। पानी कम होने के बावजूद पूरी तरह निकलने में अभी समय लग रहा है। तिगरी गंगा घाट पर भी पानी भरा होने से श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़

रहा है। स्नान के लिए पहुंचने वाले लोगों को गहरे पानी में जाने से बचने की सलाह दी जा रही है। प्रशासन और संबंधित विभाग की ओर से लोगों को गंगा में स्नान के दौरान सावधानी बरतने को कहा जा रहा है। जलस्तर ने उतार-चढ़ाव को देखते हुए गंगा किनारे रहने वाले लोगों की भी निगरानी की जा रही है।

डिडौली हादसे में मृत युवक की पहचान हुई, मुरादाबाद के गांव डेरिया दान का था निवासी

डिडौली/अमरोहा (सब का सपना):- जनपद के डिडौली कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर 25 अगस्त 2026 की रात हुए सड़क हादसे में जान गंवाने वाले अज्ञात युवक की शिनाख्त हो गई है। मृतक की पहचान बंटी पुत्र हनी सिंह के रूप में हुई है, जो मुरादाबाद जनपद के भानपुर थाना क्षेत्र के ग्राम डेरिया दान का निवासी था। पुलिस के अनुसार 25 अगस्त की रात डिडौली कोतवाली क्षेत्र के चौधरपुर स्थित नेशनल हाईवे पर एक अज्ञात वाहन ने पैदल जा रहे युवक को



टक्कर मार दी थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना की सूचना मिलते ही डिडौली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे

में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। उस समय शव की पहचान नहीं हो पाई थी। बुधवार 26 अगस्त को मृतक की पहचान हुई। मृतक के

भाई महेश ठाकुर ने बताया कि बंटी 25 अगस्त को कांवड़ लेकर घर से निकला था। रास्ते में यह हादसा हो गया। परिजनों के आने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम व अन्य कानूनी कार्रवाई पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अब हादसे के जिम्मेदार वाहन और उसके चालक की तलाश कर रही है। इसके लिए आसपास लोग सीटीटीवी और स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है।

कांवड़ यात्रा में मीट दुकानें बंद करने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, अमरोहा प्रशासन को नोटिस

अमरोहा (सब का सपना):- जनपद में कांवड़ यात्रा के दौरान मीट की दुकानें बंद करने के प्रशासन के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। सर्वोच्च अदालत ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, अमरोहा के डीएम और एसपी व इंसपेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह याचिका समाजसेवी और अधिवक्ता हाजी नासिर फारूक ने दायर की थी। अमरोहा प्रशासन ने कांवड़ यात्रा के मद्देनजर मीट, मछली और मुर्गों की दुकानों को 25 दिनों के लिए बंद करने का आदेश दिया था। याचिका में आरोप लगाया गया है कि ये



नोटिस बिना नाम और पते के जारी किए गए थे और इससे खान-पान व्यवसाय से जुड़े हजारों लोग प्रभावित हुए। याचिकाकर्ता हाजी नासिर फारूक एडवोकेट ने कहा,

"हम शिव भक्तों की आस्था का सम्मान करते हैं। जिन रास्तों से कांवड़ यात्रा गुजरती है, वहां मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए। लेकिन जिन इलाकों में शत-प्रतिशत मुस्लिम

आबादी है और जो कांवड़ मार्ग में नहीं आते, वहां इस व्यवसाय पर पूरी तरह पाबंदी लगाना न्यायसंगत नहीं है।" इससे पहले हाजी नासिर फारूक ने इसी तर्क के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि प्रभावित दुकानदारों को खुद अदालत आना चाहिए। इसके बाद नासिर फारूक ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां उनकी दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने यूपी सरकार और स्थानीय प्रशासन को नोटिस जारी किया है।

मंडी धनौरा पुलिस ने शांतिभंग में 9 लोगों का चालान कर न्यायालय भेजा

धनौरा/अमरोहा (सब का सपना):- जनपद की मंडी धनौरा पुलिस की शांति भंग के आरोप में नौ लोगों को गिरफ्तार किया है। जिनका संबंधित धाराओं में चालान करते हुए उन्हें न्यायालय में पेश किया गया है। पुलिस द्वारा इस कार्यवाही को क्षेत्र में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे अपराधों की रोकथाम और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य किया गया है। बता दें कि बुधवार को मंडी धनौरा पुलिस ने शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में नौ अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इन सभी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की संबंधित धाराओं के तहत माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। यह कार्रवाई क्षेत्र में संज्ञेय अपराधों की रोकथाम और कानून-



व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है। इसके बारे में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी सतेन्द्र सरोहा ने बताया कि पुलिस टीम क्षेत्र में संभावित अपराधों को रोकने और शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए लगातार सर्तकता बरत रही है। इसी क्रम में सांदिध गतिविधियों और शांति भंग की आशंका के चलते विभिन्न

गांवों से इन नौ लोगों को हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में ग्राम कपसुआ से सोनू पुत्र हीरा, अंकित पुत्र अर्जुन और ज्ञानी पुत्र भुर्री शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, ग्राम सुनगढ़ माफी से निजाम उर्फ निजामुद्दीन पुत्र मकबूल और ग्याशुद्दीन पुत्र निजामुद्दीन को भी गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्तों

में ग्राम मखदूमपुर (थाना नौगावा सादात) से आरिफ पुत्र शहजाद तथा ग्राम डोंगरा से अब्बार पुत्र अखतर, जावेद पुत्र अब्बार और हारून पुत्र अब्बार शामिल हैं।

इस अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक (उ०नि०) रवि कुमार, हेड कांस्टेबल करमप्रकाश और कांस्टेबल जगनप्रकाश (थाना मंडी धनौरा) प्रमुख रूप से शामिल रहे। थाना प्रभारी सतेन्द्र सरोहा ने सख्त चेतावनी दी है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बिगाड़ने या किसी भी प्रकार का संज्ञेय अपराध करने का प्रयास करने वाले असामाजिक तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस की यह कठोर दंडात्मक कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

धारदार हथियार और लाठी-डंडों से हमला करने वाले पांच आरोपी पुलिस ने किए गिरफ्तार

जुनावई/संभल (सब का सपना):- थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर-ट्रॉली में बैठे लोगों के साथ धारदार हथियार और लाठी-डंडों से मारपीट करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पांच वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की कार्रवाई से मामले में नामजद आरोपियों में खलबली मच गई। जानकारी के अनुसार मंगलवार को थाना जुनावई क्षेत्र के ग्राम घुघईया निवासी जयपाल पुत्र खुशीराम ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि अभियुक्तों ने एकराय होकर जान से मारने की नीयत से उसके तथा उसके साथ ट्रैक्टर-ट्रॉली



में बैठे अन्य लोगों के साथ मारपीट की। आरोप है कि हमले में धारदार हथियारों के साथ लाठी-डंडों का भी इस्तेमाल किया गया। घटना की

तहरीर मिलने के बाद थाना जुनावई पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। मामले की गंभीरता से लेते

हुए पुलिस टीम ने बुधवार को कार्रवाई की और मुकदमे से संबंधित वांछित पांच अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुभाष पुत्र ओमप्रकाश उम्र 29 वर्ष, महेश पुत्र ज्ञानी उम्र 45 वर्ष, वीरपाल पुत्र ज्ञानी उम्र 35 वर्ष, रामविरेश पुत्र ज्ञानी उम्र 30 वर्ष तथा चन्ना उर्फ चरन सिंह पुत्र रामवीर उम्र 26 वर्ष के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद उनके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मामले में पुलिस द्वारा घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की भी जांच की जा रही है।

पारिवारिक विवादों के समाधान को हुई काउंसलिंग, 13 मामलों में बनी सहमति

चंदौसी/संभल(सब का सपना):— जनपद के पुलिस अधीक्षक विकास चंद्र त्रिपाठी के आदेशानुसार तथा अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिण मनोज कुमार रावत एवं क्षेत्राधिकारी स्तुति सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे पुलिस परिवार परामर्श एवं सुलह-समझौता केंद्र की बैठक बुधवार को चंदौसी स्थित गौशाला रोड पिक चौकी में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता परिवार परामर्श केंद्र प्रभारी एवं महिला थानाध्यक्ष डॉ. रुकम पाल सिंह ने की। बैठक में पति-पत्नी के बीच चल रहे आपसी



विवादों को काउंसलरों के सहयोग से समझाने-बुझाने तथा सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित कराने का प्रयास किया गया। इस

कार्रवाई की संस्तुति की गई। वहीं, 12 पत्रावलियों को आवेदक द्वारा पैरवी न करने तथा अन्य कारणों के चलते बंद कर दिया गया। परिवार परामर्श केंद्र की टीम ने दंपतियों की समस्याओं को सुनते हुए आपसी मतभेद दूर कर परिवार को टूटने से बचाने के लिए समझौते का प्रयास किया। इस अवसर पर काउंसलर रवेता गुप्ता, पूनम अरोरा, उपनिरीक्षक महेश गंगवार, हेड काउंसलर मनोहर सिंह, रुचि सहित अन्य पुलिसकर्मी एवं संबंधित लोग मौजूद रहे।

रक्षाबंधन पर मातृशक्ति को उपहार, 560 महिलाओं को बांटी साड़ी और मिष्ठान

60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को मिलेगी निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा



बहजोई/संभल(सब का सपना):— रक्षाबंधन के पावन पर्व के उपलक्ष्य में बुधवार को परिवहन विभाग की ओर से इस्लामनगर रोड स्थित निजी रिसॉर्ट में रक्षाबंधन का त्योहार-मातृशक्ति को उपहार कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन गुलाब देवी ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी अंकित खण्डेलवाल के निर्देशन में मुख्य विकास अधिकारी गोरखनाथ भट्ट ने की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक गुन्गौर अजीत कुमार राजू यादव, भाजपा जिलाध्यक्ष हरेंद्र सिंह

रिंकू तथा नगर पालिका परिषद बहजोई के अध्यक्ष राजेश शंकर राजू मौजूद रहे। मुख्य विकास अधिकारी गोरखनाथ भट्ट एवं अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सत्य प्रिय सिंह ने मंत्री सहित जनप्रतिनिधियों का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने अतिथियों को राखी बांधकर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दीं और समूह द्वारा तैयार मिनी किट भी भेंट की। कार्यक्रम में मंत्री गुलाब देवी ने 560 से अधिक महिलाओं को साड़ी एवं मिष्ठान वितरित कर मातृशक्ति का सम्मान किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा लखनऊ से लोकमाता



अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना का शुभारंभ एवं विशेष बसों के फ्लैग-ऑफ कार्यक्रम का सजीव प्रसारण दिखाया गया। योजना के तहत 60 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की महिलाओं को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा रक्षाबंधन के अवसर पर 27 अगस्त सुबह छह बजे से 29 अगस्त की मध्यरात्रि 12 बजे तक माताओं, बहनों एवं बेटियों को सहायत्री सहित निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए निर्धारित पहचान पत्र दिखाना होगा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री गुलाब देवी ने महिलाओं को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दीं और

कहा कि मातृशक्ति का सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा से महिलाएं बिना आर्थिक बाधा के अपने भाइयों और परिजनों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मना सकेंगी। इस अवसर पर एसडीएम चंदौसी आशुतोष तिवारी, एआरटीओ अमिताभ चतुर्वेदी, उप कृषि निदेशक अरुण कुमार त्रिपाठी, एआरएम रोडवेज प्रेम सिंह, भाजपा जिला उपाध्यक्ष शिल्पी गुप्ता एवं विकास वार्षेय सहित प्रशासनिक अधिकारी, परिवहन विभाग के कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं।

सीएचसी रजपुरा में फामेसी ट्रेनिंग प्रमाणपत्र के नाम पर रुपये लेने का आरोप

डीएम को शिकायती पत्र देकर जांच और कार्रवाई की मांग, ऑनलाइन भुगतान के स्क्रीनशॉट होने का दावा

बहजोई/संभल(सब का सपना):— सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रजपुरा में फामेसी की तीन माह की ट्रेनिंग के प्रमाणपत्र के नाम पर छह हजार रुपये लेने और प्रशिक्षण रजिस्टर में नियमित हस्ताक्षर नहीं कराने के आरोप लगाए गए हैं। मामले में ग्राम देवरा पूरा निवासी रजनीश यादव ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। शिकायती पत्र में रजनीश यादव ने बताया कि उनका पुत्र विश्वजीत यादव सीएचसी रजपुरा में फामेसी की तीन माह की ट्रेनिंग कर रहा था। ट्रेनिंग पूरी होने



पीड़ित रजनीश यादव

के बाद जब उसने प्रमाणपत्र मांगा तो आरोप है कि सीएचसी प्रभारी पवन सिंह ने पांच हजार रुपये तथा फार्मासिस्ट नेत्रपाल सिंह ने एक हजार रुपये की मांग की।

शिकायतकर्ता का दावा है कि उक्त धनराशि ऑनलाइन संबंधित लोगों के मोबाइल नंबर पर भेजी गई। शिकायतकर्ता ने बताया कि ऑनलाइन भुगतान के स्क्रीनशॉट उसके पास सुरक्षित हैं और जांच के दौरान इन्हें साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अलावा आरोप लगाया गया कि तीन माह की ट्रेनिंग के दौरान प्रशिक्षण रजिस्टर में नियमित रूप से हस्ताक्षर नहीं कराए गए और उपस्थिति का विधिवत रिकॉर्ड भी दर्ज नहीं किया गया। शिकायती पत्र में प्रशिक्षण रजिस्टर, उपस्थिति

रिकॉर्ड, प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया तथा ऑनलाइन किए गए छह हजार रुपये के भुगतान की जांच कराने की मांग की गई है। साथ ही आरोप सही पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई करने तथा रुपये वापस दिलाने की मांग की गई है। शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी से मामले का तत्काल संज्ञान लेकर प्रशिक्षण जांच कराने का अनुरोध किया है। हालांकि, लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। जांच के बाद ही आरोपों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

जीव-जंतुओं की सेवा और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहा कालीचरण गायत्री परिवार

निस्वार्थ भाव से पशु-पक्षियों को भोजन कराने के साथ पौधरोपण कर लोगों को कर रहे जागरूक



बहजोई/संभल (सब का सपना):— जीव-जंतुओं के प्रति दया, करुणा और सेवा की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कालीचरण गायत्री परिवार बहजोई की ओर से लगातार निस्वार्थ भाव से पशु-पक्षियों और अन्य जीवों की सेवा की जा रही है। परिवार के सदस्यों का कहना है कि प्रकृति में हर जीव का अपना महत्व है और सभी को जीने का समान अधिकार है। मनुष्य को अपने स्वाद के लिए किसी जीव का भक्षण करने के बजाय उसके प्रति दया और संवेदना रखनी चाहिए। कालीचरण गायत्री परिवार द्वारा

प्रतिदिन विभिन्न स्थानों पर पशु-पक्षियों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था की जाती है। विशेष रूप से बंदरों को भोजन कराकर उनकी सेवा की जाती है। परिवार के सदस्यों का मानना है कि धार्मिक मान्यताओं में बंदरों को हनुमानजी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए उनकी सेवा करना पुण्य और मानवता का कार्य है। गर्मी के मौसम में पशु-पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करने के साथ उन्हें भोजन उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जाता है। जीव-जंतुओं की सेवा के साथ कालीचरण गायत्री परिवार पर्यावरण संरक्षण के लिए भी लगातार



कार्य कर रहा है। परिवार की ओर से विभिन्न स्थानों पर पौधरोपण कर लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सदस्यों का कहना है कि पेड़-पौधे केवल मनुष्य के लिए ही नहीं, बल्कि पशु-पक्षियों के लिए भी जीवन का आधार हैं। पेड़ों की संख्या बढ़ने से जीव-जंतुओं को आश्रय और भोजन मिलता है तथा पर्यावरण भी संतुलित रहता है। परिवार के सदस्यों ने लोगों से अपील की कि वे अपने आसपास रहने वाले पशु-पक्षियों के प्रति संवेदनशील बनें और गर्मी के दिनों में उनके लिए पानी

व दाने की व्यवस्था करें। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में पौधरोपण को प्राथमिकता देनी चाहिए। कालीचरण गायत्री परिवार का कहना है कि मानव जीवन तभी सार्थक है, जब मनुष्य अपने साथ-साथ प्रकृति और दूसरे जीवों के जीवन की भी चिंता करे। जीवों की रक्षा, सेवा और पर्यावरण संरक्षण सामूहिक जिम्मेदारी है। यदि समाज का प्रत्येक व्यक्ति छोटे स्तर पर भी इस दिशा में प्रयास करे तो पशु-पक्षियों के साथ-साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखा जा सकता है।

बहजोई में अकीदत और उत्साह के साथ निकला बारह वफात का जुलूस

इस्लामी झंडों के साथ नन्हे-मुन्ने बच्चों ने बढ़ाया जुलूस का आकर्षण, नात-ए-पाक से गुंजा नगर



बहजोई/संभल(सब का सपना):— जनपद के बहजोई नगर में बुधवार को जश्ने ईद मिलादुन्नी के मौके पर बारह वफात का जुलूस अकीदत, उत्साह और शान-ओ-शौकत के साथ निकाला गया। जुलूस को लेकर सुबह से ही मुस्लिम समुदाय के लोगों में ख़ासा उत्साह नज़र आया। बड़ी संख्या में लोगों ने जुलूस में शामिल होकर पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रति अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया। बारह वफात का जुलूस बहजोई के मदीना मस्जिद से शुरू हुआ। जुलूस कुरैशियान मोहल्ला, स्टेशन रोड, सैफियान मस्जिद, गौसिया मोहल्ला समेत नगर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरा। इस दौरान जगह-जगह लोगों ने जुलूस का अकीदत के साथ स्वागत किया। जुलूस में शामिल लोग



नात-ए-पाक पेश करते हुए तथा आका की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे, जिससे पूरा माहौल धार्मिक उत्साह से गुंज उठा। जुलूस में नन्हे-मुन्ने बच्चे विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। बच्चे हाथों में इस्लामी झंडे और बैनर लेकर उत्साह के साथ जुलूस में शामिल हुए। वहीं बड़ी संख्या में बुजुर्ग और युवा भी जुलूस में मौजूद रहे। कई स्थानों पर लोगों ने जुलूस में शामिल अकीदतमंदों के लिए शरबत, पानी और खाने-पीने की वस्तुओं का वितरण किया। इसके अलावा संभल रोड स्थित चित्तौरी रोड पर मोहम्मद उमर एडवोकेट की अध्यक्षता में भी जश्ने ईद मिलादुन्नी का आयोजन किया गया। कुरैशियान मोहल्ले में मदीना मस्जिद से जुलूस निकाला गया। टंकी मोहल्ला और अल्वी नगर में भी जश्ने ईद मिलादुन्नी की लेकर विशेष आयोजन हुए। जुलूस में काबा शरीफ, मदीना शरीफ और अजमेर

शरीफ सहित विभिन्न मुकद्दस स्थलों के प्रतीकात्मक स्वरूप भी शामिल रहे, जिन्हें देखने के लिए मार्ग में लोगों की भीड़ दिखाई दी। आयोजकों ने कहा कि जश्ने ईद मिलादुन्नी का उद्देश्य पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की सिरत और उनकी शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाना है। उन्होंने अमन, भाईचारे, ईसाफ, रहमत और इंसानियत का संदेश दिया। जुलूस में शामिल लोगों ने आपसी भाईचारे और सौहार्द बनाए रखने का संदेश भी दिया। जुलूस निर्धारित मार्गों से होता हुआ वापस मदीना मस्जिद पहुंचा, जहां उसका समापन किया गया। इस दौरान टंकी मोहल्ला, अल्वी नगर, कुरैशियान मोहल्ला, पच्चीसा कॉलोनी सहित नगर के विभिन्न क्षेत्रों में ईद मिलादुन्नी को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिला।

1500 रुपये की नौकरी से 55 हजार रुपये महीने के कारोबार तक पहुंची महिला

एनआरएलएम ने बदली ग्रामीण महिला की ज़िंदगी, लड्डू और नमकीन के कारोबार से बनीं आत्मनिर्भर



बहजोई/संभल(सब का सपना):— आर्थिक तंगी और संघर्षों को मात देकर बनिगाखेड़ा ब्लॉक के ग्राम जैरोई हयात नगर निवासी 35 वर्षीय अनुपम ने ग्रामीण महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश की है। कभी निजी स्कूल में महज 1500 रुपये के मानदेय पर पढ़ाने वाली अनुपम आज राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के सहयोग से हर महीने करीब 50 से 55 हजार रुपये का कारोबार कर रही हैं। बीए पास अनुपम वर्ष 2020 के लोकडाउन से पहले अपने पति के साथ गांव के निजी विद्यालय में बच्चों को पढ़ाती थीं। लोकडाउन में स्कूल बंद होने से रोजगार छिन गया और परिवार आर्थिक संकट में आ गया। इसी दौरान उन्होंने एनआरएलएम के तहत गठित संजीवन स्वयं सहायता समूह की सदस्यता ली। वर्ष 2021 में समूह



के माध्यम से 70 हजार रुपये का ऋण लेकर ब्यूटी पालर और जनरल स्टोर शुरू किया। मेहनत के दम पर उन्होंने 10 महीने की निर्धारित अवधि से पहले ही महज आठ महीने में पूरा ऋण चुका दिया और 20 हजार रुपये की बचत भी की। कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए अनुपम ने ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) से 20 दिन का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद वर्ष 2024 में सीआईएफ फंड से 50 हजार रुपये का ऋण लेकर मनुमाना, रागी, ज्वार और बाजरा से मल्टीग्रेन पाैटिक लड्डू तथा घर में भुने देसी चने की नमकीन बनाने का काम शुरू किया। उत्पादों की गुणवत्ता देखकर प्रशासनिक अधिकारियों ने भी उनके उत्पादों को बढ़ावा दिया। नवंबर 2024 से चंदौसी के 12 इंटर कॉलेजों में बच्चों के लिए करीब 2.80 लाख रुपये के लड्डूओं की

आपूर्ति की गई। इसके अलावा कलेक्ट्रेट में होने वाली बैठकों और विभिन्न आयोजनों में भी उनके उत्पादों की मांग होने लगी। अनुपम के उत्पाद संभल के अलावा मुरादाबाद और अमरौहा तक पहुंच रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर अमरौहा में उनके समूह ने 22,600 रुपये के उत्पादों की बिक्री की। वर्ष 2025 में संभल जिले में 3.86 लाख रुपये से अधिक के उत्पाद बेचे गए। प्रशासनिक आयोजनों के ऑर्डर पर करीब 20 प्रतिशत तक शुद्ध मुनाफा भी प्राप्त होता है। संजीवन स्वयं सहायता समूह में 10 महिलाएं हैं। बड़े ऑर्डर मिलने पर अनुपम समूह की अन्य महिलाओं को भी काम देकर उन्हें पारिश्रमिक देती हैं। इससे गांव की अन्य महिलाएं भी रोजगार से जुड़ रही हैं। रक्षाबंधन के अवसर पर अनुपम को कलेक्ट्रेट सभागार में स्टॉल लगाने का अवसर

चीनी के भंडारण पर प्रशासन की नजर, व्यापारियों के प्रतिष्ठानों का किया निरीक्षण

4000 क्विंटल से अधिक स्टॉक रखने पर रोक, पोर्टल पर पंजीकरण और स्टॉक घोषित करना अनिवार्य



बहजोई/संभल(सब का सपना):— चीनी की उपलब्धता एवं आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने और अनावश्यक भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन ने निगरानी तेज कर दी है। जिलाधिकारी अंकित खण्डेलवाल ने संबंधित अधिकारियों को चीनी के स्टॉक एवं उपलब्धता की नियमित निगरानी करने तथा निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। शासन से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में चीनी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और आपूर्ति व्यवस्था सामान्य है। निर्धारित व्यवस्था के तहत कोई भी चीनी डीलर एक स्थान पर एक समय में



4000 क्विंटल से अधिक चीनी का स्टॉक नहीं रख सकेगा। सरकारी खातों तथा राज्य सरकार द्वारा नामित डीलरों अथवा अधिकृत अधिकारियों के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित दर दुकानों को आपूर्ति की जाने वाली चीनी के स्टॉक पर यह सीमा लागू नहीं होगी। सभी चीनी डीलरों के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के स्टॉक मॉनिटरिंग पोर्टल foodstock.dfpd.gov.in पर पंजीकरण कर अपने चीनी स्टॉक की स्थिति घोषित करना अनिवार्य किया गया है। डीएम के निर्देश पर तहसील सम्भल और चंदौसी में चीनी डीलरों, स्टॉक और थोक एवं खुदरा विक्रेताओं की

दुकानों और गोदामों के निरीक्षण के लिए एसडीएम के नेतृत्व में संयुक्त टीमों गठित की गई हैं। इसी क्रम में मंगलवार को दोनों तहसीलों में चीनी व्यापारियों के प्रतिष्ठानों और फर्मों का निरीक्षण किया गया। चंदौसी में एसडीएम आशुतोष तिवारी के नेतृत्व में किए गए निरीक्षण के दौरान मैसर्स गोपाल ट्रेडिंग, मैसर्स कुन्दन लाल तोताराम, मैसर्स अमृत लाल किशन लाल, मैसर्स मनोहर लाल अशोक कुमार, मैसर्स मिश्री लाल सुख लाल तथा मैसर्स ओम एंड संस में निर्धारित सीमा के अंतर्गत स्टॉक पाया गया। वहीं मैसर्स भजनलाल रामेश्वर दास का पंजीकरण न होने और पोर्टल पर स्टॉक दर्ज नहीं किए जाने पर नोटिस जारी किया गया। सम्भल में एसडीएम विकास चन्द्र ने चीनी व्यापारियों के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। मैसर्स कुमार एंटरप्राइजेज, मैसर्स सुभाष तथा मैसर्स योगेश कुमार अमित के प्रतिष्ठानों की जांच के दौरान पोर्टल पर पंजीकरण और स्टॉक की जानकारी पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। निर्धारित स्टॉक सीमा, पोर्टल पर पंजीकरण अथवा स्टॉक घोषणा संबंधी नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

'मान्यता प्राप्त' और 'अप्रूव्ड' शब्द पर रोक, हरियाणा में कोचिंग संस्थानों के लिए नई पॉलिसी लागू

चंडीगढ़। हरियाणा के उच्च शिक्षा विभाग ने निजी कोचिंग संस्थानों के संचालन को लेकर नियमों को अब स्पष्ट रूप से लागू करने की व्यवस्था कर दी है। विभाग ने 24 अगस्त 2026 को हरियाणा प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स (रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन) रूल्स, 2026 की अधिसूचना जारी की है। ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे। नई व्यवस्था के तहत पहले से चल रहे और नए स्थापित होने वाले प्रत्येक निजी कोचिंग संस्थान को संबंधित जिला प्राधिकरण के निर्धारित पोर्टल पर फार्म-1 के पार्ट-1 और पार्ट-2 में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके साथ 10 हजार रुपये रजिस्ट्रेशन फीस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जमा करनी होगी। जिला प्राधिकरण आवेदन की 30 दिन में जांच करेगा। कमी मिलने पर संस्थान को उसे दूर करने के लिए 10 दिन का समय दिया जाएगा। आवेदन पूरा पाए जाने पर रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र जारी होगा, जिसकी वैधता तीन वर्ष होगी। मान्यता प्राप्त शब्द नहीं कर सकते इस्तेमाल नए नियमों में कोचिंग संस्थानों के प्रचार को लेकर भी महत्वपूर्ण प्रविधान किया गया है। संचालक को केवल "रजिस्टर्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट" शब्द का इस्तेमाल करना होगा। साइन बोर्ड, प्रास्पेक्टस या किसी भी प्रकार के प्रचार-प्रसार में "संबद्ध" या "मान्यता प्राप्त" शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इसके



अलावा स्कूल या किसी शिक्षण संस्थान में पढ़ रहे विद्यार्थियों की कोचिंग कक्षाएं उनके स्कूल/संस्थान के अध्ययन या कार्य समय के दौरान नहीं चलाने की शर्त रखी गई है। कोचिंग संस्थान को शिक्षकों की योग्यता, कक्षा की समय-सारणी, फीस स्ट्रक्चर और सामान्य जानकारी वेबसाइट तथा संस्थान के प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करनी होगी। फीस, रिफंड और "ईजी एग्जिट" का ब्यौरा देना होगा रजिस्ट्रेशन आवेदन के साथ संस्थान को अपने पाठ्यक्रम की जानकारी, उसे पूरा करने की अवधि, ट्यूशन फीस समेत सभी प्रकार की फीस, फीस रिफंड पॉलिसी, ईजी एग्जिट, लेजर, ट्यूटोरियल, ग्रुप डिस्कशन और टेस्ट शेड्यूल की जानकारी देनी होगी। प्रत्येक बैच में अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या तथा

शिक्षकों और काउंसलर की शैक्षणिक योग्यता और बायोडेटा भी देना होगा। कोचिंग सेंटर में सुविधाओं की भी होगी जांच आवेदन में संस्थान को फर्नीचर, रोशनी, पीने का पानी, पुरुष और महिला के लिए अलग शौचालय, अग्नि सुरक्षा, प्राथमिक चिकित्सा, फर्किंग, पुस्तकालय/रीडिंग रूम, वाई-फाई, स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर लैब, हॉस्टल और कैंटीन जैसी सुविधाओं की स्थिति बतानी होगी। इसके साथ ही स्टाफ के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के पुलिस सत्यापन, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, स्ट्रक्चर स्ट्रेबिलिटी सर्टिफिकेट और दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए भवन के बाधारहित होने की जानकारी भी देनी होगी। हर साल रिकॉर्ड रखना और वेबसाइट पर अपलोड करना जरूरी अधिनियम के तहत पंजीकृत प्रत्येक निजी

कोचिंग संस्थान को फार्म-4 में निर्धारित रिकॉर्ड रखना और अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। इसकी जानकारी हर वर्ष संबंधित जिला प्राधिकरण को देनी होगी। रिकॉर्ड में भवन का मालिकाना/किराये का दस्तावेज, कुल क्षेत्रफल, बैचवार विद्यार्थियों की संख्या, छात्रों की उम्र-योग्यता-संपर्क

विवरण, पाठ्यक्रम और फीस, फीस रिफंड नीति, शिक्षकों का पूरा विवरण, टाइम टेबल, कोचिंग लेने वाले और सफल विद्यार्थियों का विवरण, वेबसाइट अपडेट का अंतराल, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा, हास्टल शुल्क, शिकायत निवारण व्यवस्था और चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट किए गए वार्षिक खाते शामिल होंगे।

आज ही निपटा लें काम ! पंजाब में कल कर्मचारियों की हड़ताल, चार दिन प्रभावित रहेगा सरकारी कामकाज
चंडीगढ़। लॉबित महंगाई भत्ते (डीए), पुरानी पेंशन योजना समेत विभिन्न मांगों को लेकर पंजाब के सरकारी कर्मचारी 27 अगस्त को प्रदेशव्यापी हड़ताल करेंगे। कर्मचारी संगठनों के अनुसार करीब तीन लाख कर्मचारी सामूहिक अवकाश लेकर प्रदर्शन में शामिल होंगे, जबकि बड़ी संख्या में पेंशनर भी आंदोलन का समर्थन करेंगे। पंजाब सांझा मुलाजिम मंच के नेता सुखचैन सिंह खेहर के अनुसार 27 अगस्त को सचिवालय से लेकर जिला स्तर तक सरकारी कार्यालयों में कामकाज बंद रहेगा। उपायुक्त, एसडीएम, तहसील और राजस्व कार्यालयों के अलावा परिवहन, स्वास्थ्य, स्कूल और कॉलेजों के कर्मचारी भी आंदोलन में शामिल होंगे। स्वास्थ्य संस्थानों में आपात सेवाएं जारी रखने की बात कही गई है। कर्मचारियों की क्या हैं मांगें? कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में लॉबित 18 प्रतिशत डीए की किस्से व बकाया जारी करना, पुरानी पेंशन योजना बहाल करना, ठेका कर्मचारियों को नियमित करना और अन्य सेवा संबंधी मांगें शामिल हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने भी लॉबित डीए के भुगतान को लेकर राज्य सरकार को निर्देश दिए थे। 27 अगस्त के बाद 28 अगस्त को रक्षाबंधन का सरकारी अवकाश है और इसके बाद शनिवार-रविवार होने के कारण लगातार कई दिनों तक नियमित सरकारी कामकाज प्रभावित रहने की आशंका है। हड़ताल के कारण बाधित रहेंगे सभी काम 28 अगस्त को रक्षा बंधन अवकाश और शनिवार और रविवार छुट्टी रहेगी। कल हड़ताल के कारण रजिस्ट्रियों, प्रमाणपत्रों, राजस्व मामलों और अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए सरकारी कार्यालयों में पहुंचने वाले लोगों को परेशानी हो सकती है।

पंजाब में 1100 शिक्षकों की बल्ले-बल्ले, मान सरकार ने वेतन में की बंपर बढ़ोतरी; हर महीने अब कितनी मिलेगी सैलरी?

चंडीगढ़। राज्य सरकार ने आदर्श स्कूलों में सेवाएं दे रहे शिक्षकों के वेतन में 120 प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान कहा कि सरकार के इस फैसले से प्रदेश के करीब 1,100 शिक्षकों को लाभ मिलेगा। इन शिक्षकों का मासिक वेतन करीब 10 हजार रुपये से बढ़कर 22 हजार रुपये से अधिक हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को यह निर्णय शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद लिया। उन्होंने कहा कि शिक्षक शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ हैं और उन्हें सम्मान के साथ उचित वेतन मिलना चाहिए। इसीलिए करीब दो दशक से कम वेतन पर सेवाएं दे रहे आदर्श स्कूलों के शिक्षकों की जायज मांग को सरकार ने स्वीकार किया है। बेहतर शिक्षा देने में अधिक प्रभावी भूमिका



मुख्यमंत्री ने कहा कि सीबीएसई से मान्यता प्राप्त इन आदर्श स्कूलों में 15 हजार से अधिक विद्यार्थी शिक्षा हासिल कर रहे हैं। ऐसे में शिक्षकों को आर्थिक सुरक्षा और बेहतर सेवा सुविधाएं उपलब्ध कराना विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब शिक्षक सुरक्षित और सम्मानित महसूस करेंगे तो वे

मजबूत करने के साथ प्रदेश के प्रत्येक विद्यार्थी का भविष्य सुरक्षित करना है। केन्द्रीय विद्यालयों की तर्ज पर मिलेंगी सुविधाएं मुख्यमंत्री ने कहा कि वेतन बढ़ोतरी के साथ शिक्षकों को केन्द्रीय विद्यालयों की तर्ज पर सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

इससे उनकी सेवा शर्तों में सुधार होगा और उन्हें बेहतर कार्य वातावरण मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और कर्मचारियों के हितों की अनदेखी नहीं की जाएगी। बैठक में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बंस, मुख्य सचिव केएपी सिन्हा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव डा. रवि भगत, स्कूल शिक्षा सचिव सोनाली गिरि सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

मानसा जेल के 69% कैदी नशे की चपेट में, हाई कोर्ट ने सभी जेलों की मांगी डिटेल; मान सरकार पर उठाए कई सवाल

चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने जेलों में बंद नशे के आदी कैदियों के उपचार और पुनर्वास के संबंध में पंजाब सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी है। कोर्ट ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (जेल) को निर्देश दिया है कि वे प्रदेश की सभी जेलों में आउट-पेशेंट ओपिओइड असिस्टेड ट्रीटमेंट (ओओएटी) ले रहे कैदियों का जेलवार ब्यौरा हलफनामा के माध्यम से प्रस्तुत करें। इसके साथ ही, कोर्ट ने यह भी पूछा है कि नशे पर निर्भर कैदियों को दवाओं से धीरे-धीरे बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कुमार की खंडपीठ ने मानसा सेशन डिवीजन के प्रशासनिक न्यायाधीश की रिपोर्ट के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दर्ज की थी। रिपोर्ट के



अनुसार, मानसा जेल में कुल 767 कैदी बंद थे, जिनमें से 530 ओओएटी क्लीनिक में पंजीकृत थे, जोकि लगभग 69 प्रतिशत है। इसे कैदियों में नशे की लत की गंभीरता का संकेत माना गया है। कैदियों को दी जा रही ये दवाई खंडपीठ ने राज्य सरकार से ओओएटी क्लीनिक में कैदियों के पंजीकरण से संबंधित

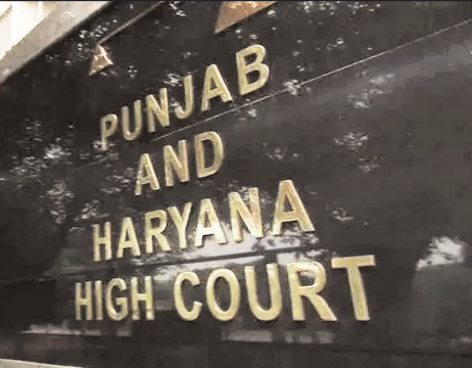


फॉलोअप के संबंध में चिंता व्यक्त की थी। रिपोर्ट में ब्यूरोफॉर्म-नालोक्सोन उपचार पूरा कर दवा बंद करने के चरण तक पहुंचने वाले लोगों का आंकड़ा मांगा गया था। नशे के चक्र में न फंसे हाई कोर्ट ने जेलों और निजी ओपिओइड उपचार केंद्रों में योग्य मनोचिकित्सकों, नर्सों और मनोसामाजिक सहायता की उपलब्धता का ब्योरा भी मांगा है। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि जेल से रिहा होने के बाद कैदियों को किस प्रकार सहायता दी जाएगी, ताकि वे पुनः नशे के चक्र में न फंसे। खंडपीठ ने अधिकांश तनु बेदी को एमिकस क्यूरी नियुक्त करते हुए कहा कि वे पंजाब की जेलों में बंद कैदियों की बेहदारी के लिए सुझावात्मक कदम सुझाने में कोर्ट की सहायता करेंगी। मानसले की अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी।

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में झूठा बयान देना पड़ा भारी, अरकपर लटकी कार्रवाई की तलवार; हिसार SP को दिए जांच के आदेश

चंडीगढ़। हिसार में एक मामले की जांच में शामिल होने को लेकर पुलिस और याचिकाकर्ता के दावों में विरोधाभास सामने आने पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। हाई कोर्ट ने प्रथम दृष्टया पाया कि राज्य के वकील की ओर से सहायक उपनिरीक्षक संदीप बांगर के निर्देश पर दिया गया बयान गलत प्रतीत होता है। कोर्ट ने जांच अधिकारी के आचरण को अवमानना की सीमा पर बताते हुए पुलिस अधीक्षक, हिसार को पूरे मामले की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस एनएस शेखावत की पीठ ने हरजिंदर सिंह उर्फ वरिंद कुमार की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किया। सरकार की ओर से कोर्ट को

बताया गया कि याचिकाकर्ता 14 अगस्त 2026 को मामले की जांच में शामिल होने के लिए थाने आया था। हालांकि, उसने जांच अधिकारी को दोबारा लौटकर आने का आश्वासन दिया और वहां से चला गया। इसके बाद याचिकाकर्ता को कई नोटिस जारी किए गए, लेकिन उसने जांच में शामिल नहीं हुआ। वहीं, याचिकाकर्ता के वकील ने इस दावे को गलत बताया। उन्होंने कहा कि 20 जुलाई 2026 को हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में याचिकाकर्ता ने जांच अधिकारी संदीप बांगर से उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क किया था, लेकिन जांच अधिकारी ने उसे कोई नोटिस नहीं दिया। इसके बाद 14 अगस्त को



याचिकाकर्ता स्वयं वकील के साथ सिविल लाईंस, हिसार स्थित पुलिस थाने पहुंचा था। पांच लाख रुपये देने का बनाया दबाव याचिकाकर्ता के अनुसार, वहां जांच अधिकारी ने उसे कुछ लिखित सवाल दिए, जिनके

उसने लिखित जवाब दिए। आरोप है कि इसके बाद जांच अधिकारी ने शिकायतकर्ता को पांच लाख रुपये देने का दबाव बनाया और अनुसार, वहां जांच अधिकारी ने उसे जांच में शामिल होने की अनुमति नहीं दी

जाएगी। याचिकाकर्ता और उसके वकील को रात नौ बजे तक थाने में बैठाए रखा गया। इसके बावजूद जांच अधिकारी ने याचिकाकर्ता के जांच में शामिल होने का कोई दैनिक रोजनामचा क्रमांक देने से इनकार कर दिया और उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। याचिकाकर्ता ने पुलिस अधीक्षक, हिसार को भी शिकायत देकर जांच अधिकारी को उसे जांच में शामिल करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। उसके वकील ने तस्वीरें भी पेश कीं, जिनमें याचिकाकर्ता सिविल लाईंस, हिसार थाने में दिखाई दे रहा है। निर्देश में दिया गया बयान झूठा: हाई कोर्ट मामले पर कड़ी दिपण्णी करते हुए हाई कोर्ट ने कहा, प्रथम दृष्टया, राज्य के

वकील द्वारा सहायक उपनिरीक्षक संदीप बांगर के निर्देश पर लिया गया बयान झूठा है और इस मामले में जांच अधिकारी का आचरण अवमानना की सीमा पर है। कोर्ट ने अवमानना की कार्यवाही शुरू करने से पहले पुलिस अधीक्षक, हिसार और जांच अधिकारी संदीप बांगर को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। पुलिस अधीक्षक को अगली तारीख से पहले मामले की जांच करने तथा याचिकाकर्ता के आरोप सही पाए जाने पर जांच अधिकारी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त 2026 को होगी।

पंजाब में 63 हजार परिवारों को राहत ! बिल कितना भी आए, नहीं बंद होगी 300 यूनिट मुफ्त बिजली



चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने बिजली के बढ़े हुए और अस्थायी बिलों को लेकर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। बिजली मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने कहा कि मीटर रीडरों की हड़ताल के दौरान अस्थायी बिलिंग से प्रभावित 63,702 पात्र उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ नहीं खोना पड़ेगा। बिलिंग में तकनीकी या अन्य गलती के कारण किसी पात्र परिवार को इस सुविधा से वंचित नहीं किया जाएगा। मंत्री सौंद ने बताया कि अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच मीटर रीडरों की हड़ताल के कारण कई उपभोक्ताओं के वास्तविक मीटर की रीडिंग समय पर नहीं हो सकी। ऐसे में पिछले औसत बिजली उपभोग के आधार पर अस्थायी बिल जारी किए गए। बाद में वास्तविक रीडिंग मिलने पर पिछली अवधि की खपत का समायोजन किया गया। इससे कुछ उपभोक्ताओं के बिल सामान्य से काफी अधिक दिखाई देने लगे। उन्होंने कहा कि कुल 78 लाख उपभोक्ताओं में से 63,702 उपभोक्ता इस तरह की अस्थायी बिलिंग से प्रभावित हुए हैं। पात्र उपभोक्ताओं के लिए संबंधित अवधि का 300 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ सुरक्षित रखा जाएगा। सौंद ने बताया कि वर्ष 2026 में बिलिंग संबंधी समस्याओं का एक प्रमुख कारण जनवरी में पुरानी अलग-अलग बिलिंग व्यवस्थाओं से एकीकृत एकल बिलिंग प्णाली में बदलाव भी रहा। इस दौरान बड़ी मात्रा में उपभोक्ता और बिलिंग आंकड़ों के स्थानांतरण में कुछ तकनीकी खामियां सामने आईं। कुछ मामलों में पिछली मीटर रीडिंग सही तरीके से उपलब्ध नहीं होने के कारण खपत की गणना में गड़बड़ी हुई। इन तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए आवश्यक सुधार कर दिए गए हैं। अब नई व्यवस्था के तहत सामान्य खपत से असामान्य रूप से अधिक खपत दिखाने वाले बिल स्वतः चिह्नित होंगे और जांच के बाद ही जारी किए जाएंगे।

रियल एस्टेट घोटाला: ED ने अब IAS अनुराग वर्मा को किया तलब, जालंधर कार्यालय में होंगे पेश; कंवलप्रीत को भी दोबारा बुलाया



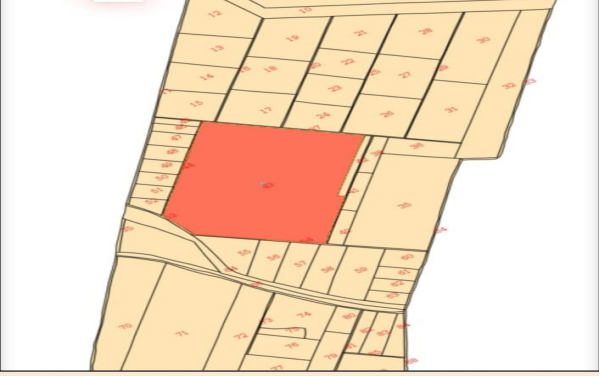
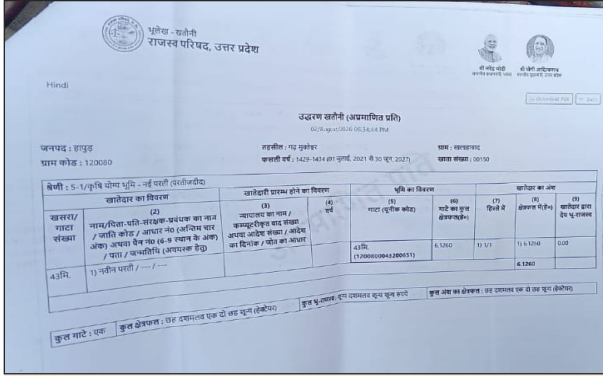
चंडीगढ़। पंजाब में कथित रियल एस्टेट घोटाले और मनी लांड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने प्रदेश के वरिष्ठ आइएएस अधिकारी अनुराग वर्मा को तलब किया है। पूर्व मुख्य सचिव और वर्तमान में अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) के पद पर तैनात अनुराग वर्मा को 31 अगस्त को जालंधर स्थित जौनल कार्यालय में पेश होने के लिए समन भेजा गया है। वहीं, आइएएस अधिकारी कंवलप्रीत बराड़ को भी 27 अगस्त को पेश होने के लिए कहा गया है। सुत्रों के अनुसार, दोनों अधिकारियों को पंजाब में कथित रियल एस्टेट अनियमितताओं से जुड़े मामले की जांच के सिलसिले में बुलाया गया है। ईडी ने हाल ही में सनटेक सिटी, अल्टस स्पेस बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड और धीर कंस्ट्रक्शंस समेत कई कंपनियों से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की थी। जांच एजेंसी अब इन परियोजनाओं में अधिकारियों की भूमिका और कथित नियम उल्लंघन की पड़ताल कर रही है। यह पहली बार है जब ईडी ने वरिष्ठ आइएएस अधिकारी अनुराग वर्मा को इस मामले में पूछताछ के लिए तलब किया है। वर्मा उस समय आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रमुख थे, जब कथित अनियमितताएं हुईं। 2007 बैच के आइएएस अधिकारी कंवलप्रीत बराड़ को ईडी पहले 18 अगस्त को जालंधर कार्यालय में पूछताछ के लिए बुला चुकी है। तब उनसे करीब नौ घंटे तक पूछताछ हुई थी। इस बार बराड़ को मामले से संबंधित अतिरिक्त दस्तावेज साख लाने के निर्देश दिए गए हैं। बराड़ वर्ष 2024 में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के निदेशक के पद पर तैनात थे और वर्तमान में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव हैं। ईडी यह पता लगाने में जुटी है कि सीएलयू मंजूरी और लेआउट में बदलाव से जुड़े फैसलों में कहीं नियमों की अनदेखी तो नहीं हुई।

हरियाणा में रक्षा बंधन पर सादी वर्दी में तैनात रहेंगी महिला पुलिस, जानें सख्ती बांधने का शुभ मुहूर्त



फतेहाबाद। रक्षाबंधन पर्व को लेकर शहर के बाजारों में बुधवार को हलचल बढ़ गई। बहनें भाइयों के लिए राखी, मिठाई और उपहार खरीदने के लिए बाजार पहुंचीं। त्योहार को लेकर बाजारों में रौनक तो बढ़ी, लेकिन महंगाई ने खरीदारी का बजट भी बिगाड़ दिया। चीनी और अन्य कच्चे माल के दाम बढ़ने के कारण मिठाइयों 30 से 50 रुपये प्रति किलो तक महंगी हो गई हैं। रक्षाबंधन पर सबसे अधिक खरीदे जाने वाले ग्वार पेटे का भाव भी 100 रुपये से बढ़कर 150 रुपये किलो तक पहुंच गया है। वहीं, त्योहार पर बाजारों में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए पुलिस और रोडवेज विभाग ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वीरवार दोपहर 12 बजे से महिलाओं को रोडवेज बसों में निशुल्क सफर की सुविधा मिलेगी। महिलाएं अपने बच्चों के साथ इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगी। बाजारों की सुरक्षा के लिए करीब 500 पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। हिसार और सिरसा रूट पर सवारियों की संख्या बढ़ने पर रोडवेज विभाग 20 अतिरिक्त फेरें भी लगाएगा। वहीं बाजारों में सफाई न होने के कारण रौनक को फीका कर दिया है। महंगाई ने फीकी की मिठाई की मिठास रक्षाबंधन पर मिठाई की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ रही है, लेकिन बढ़े हुए दाम लोगों की जेब पर भारी पड़ रहे हैं। दुकानदारों के अनुसार चीनी सहित अन्य कच्चे माल की कीमत बढ़ने के कारण मिठाइयों के दाम बढ़ाने पड़े हैं। कई मिठाइयों 30 से 50 रुपये किलो तक महंगी हो गई हैं। ग्वार पेटे की मांग रक्षाबंधन पर सबसे अधिक रहती है। कुछ दिन पहले तक करीब 100 रुपये किलो बिकने वाला ग्वार पेटा अब 150 रुपये किलो तक पहुंच गया है। महंगाई के कारण ग्राहक पहले की अपेक्षा कम मात्रा में मिठाई खरीद रहे हैं। सादी वर्दी में महिला पुलिसकर्मी रखेंगी नजर बाजारों में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। प्रमुख बाजारों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर करीब 500 पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। पुलिसकर्मी गश्त करने के साथ सौंदर्य गतिविधियों पर नजर रखेंगे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला पुलिस कर्मचारियों को सादी वर्दी में तैनात किया जाएगा। ये कर्मचारी छेड़छाड़, जेब कटने, मोबाइल चोरी और अन्य घटनाओं पर नजर रखेंगी। पुलिस का उद्देश्य त्योहार के दौरान बाजारों में सुरक्षित माहौल बनाए रखना है। ये है शुभ मुहूर्त 28 अगस्त, शुक्रवार को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार राखी बांधने का शुभ समय सुबह 6 बजकर 2 मिनट से 9 बजकर 48 मिनट तक बताया गया है। पूर्णिमा तिथि सुबह 9 बजकर 48 मिनट पर समाप्त होगी। भद्रा भी सूर्योदय से पहले समाप्त हो चुकी होगी। हालांकि धार्मिक मान्यताओं को मानने वाले परिवार अपने-अपने पंचांग और परंपरा के अनुसार समय तय कर सकते हैं। ब्रेसलेट से पर्सनलाइज्ड राखी तक छाया ट्रेड इस बार बाजार में पारंपरिक राखियों के साथ नए डिजाइन भी बहनों को आकर्षित कर रहे हैं।

गढ़मुक्तेश्वर में 255 बीघा में अवैध प्लाटिंग का खेल, प्रशासन मौन



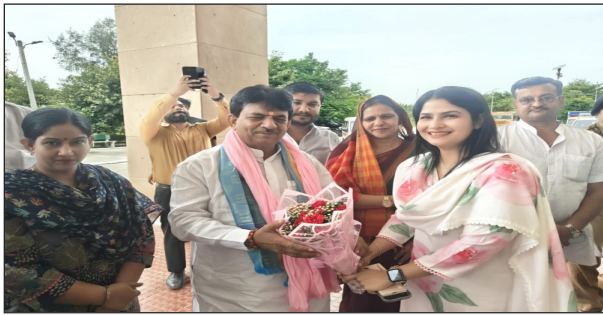
गढ़मुक्तेश्वर/हापुड (सब का सपना) ब्यूरो :- जनपद हापुड की तहसील गढ़मुक्तेश्वर व नगर पालिका गढ़मुक्तेश्वर के अंतर्गत सालाहाबाद ग्राम के रकबे में लगभग 255 बीघा जमीन पर अवैध तरीके से प्लाटिंग का बड़ा खेल चल रहा है। यह मामला सिर्फ अवैध कॉलोनी काटने तक सीमित नहीं है, बल्कि भूमि के वगीकरण में हेरफेर, खादर की बाढ़ प्रभावित जमीन पर निर्माण, गंगा से निकलने वाले प्राकृतिक नाले को बंद करने और प्रशासन की संदिग्ध भूमिका जैसे कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।

श्रेणी-5 से श्रेणी-2 कैसे बनी जमीन?
सूत्रों के मुताबिक यह भूमि कुछ वर्ष पूर्व तक राजस्व अभिलेखों में श्रेणी-5 अर्थात नवीन परती के रूप में दर्ज थी। राजस्व संहिता के जानकारों के अनुसार श्रेणी-5 की जमीन ग्राम सभा की संपत्ति होती है, जिस पर किसी भी प्रकार के निजी स्वामित्व, निर्माण या विक्रय की अनुमति नहीं होती है। ऐसी जमीन को पट्टा या अन्य प्रक्रिया के तहत ही आवंटित किया जा सकता है। लेकिन इस जमीन को बाद में तहसील प्रशासन



है।
कई अनुत्तरित सवाल
अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब वन विभाग के अधिकारी ही कह रहे हैं कि यह जमीन वन विभाग के अंतर्गत नहीं आती और दूसरी तरफ एसडीएम गढ़मुक्तेश्वर कह रहे हैं कि यह जमीन वन विभाग के अंतर्गत है, तो आखिर यह 255 बीघा जमीन किसके अंतर्गत आती है? गंगा से निकलने वाले प्राकृतिक नाले को बंद करने की परमिशन आखिर किसने दी? क्या इसके लिए सिंचाई विभाग या एनजीटी से अनुमति ली गई? खादर की जमीन में जहां दूर वर्ष बाढ़ आती हो, वहां पर बिना लेआउट पास कराए प्लाटिंग का कार्य कैसे शुरू हो गया? क्या इस जमीन का भू-उपयोग परिवर्तन कराया गया है? ऐसे अनेकों सवाल हैं जिनका जवाब जिला प्रशासन को देना होगा। लोगों की गाढ़ी कमाई इस तरह बाढ़ की जमीन में फंसने से बचाने के लिए प्रशासन को तुरंत इस मामले का संज्ञान लेकर जांच करानी चाहिए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।

मातृशक्ति को मिला सम्मान, बसों में निःशुल्क यात्रा शुरू



हापुड (सब का सपना) बाबर अली:- कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में महिलाओं/मातृशक्ति के लिए निःशुल्क यात्रा योजना का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का सजीव प्रसारण सभागार में उपस्थित महिलाओं को दिखाया गया। उसके बाद मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने महिलाओं को रक्षाबंधन के उपहार स्वरूप साड़ी और मिष्ठान देकर सम्मानित किया। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप नारी सम्मान एवं सशक्तिकरण की दिशा में प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर 27 अगस्त से 29 अगस्त की मध्यरात्रि तक प्रदेश की सभी महिलाओं,



माताओं और बहनों को एक सहवात्री के साथ UPSRTC की सभी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई है। उन्होंने बताया कि 29 अगस्त के बाद 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं को आजीवन निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा मिलेगी। यात्रा के समय केवल आधार कार्ड दिखाना होगा। उन्होंने कहा कि यह योजना केवल निःशुल्क यात्रा नहीं, बल्कि मातृशक्ति को सम्मान देने का प्रतीक है। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा नागर, जिलाधिकारी कविता मीना, एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह, सीडीओ सुश्री श्रुति शर्मा, जिला अध्यक्ष भाजपा कविता माधुर्य, एआरएम रोडवेज, पुलिस क्षेत्राधिकारी, सांसद प्रतिनिधि सहित संबंधित अधिकारी एवं भारी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं।

फतेहपुर में अपना दल एस महिला मंच की समीक्षा बैठक सम्पन्न

फतेहपुर (सब का सपना):- बुधवार को जिला अपना दल एस कार्यालय चित्रांश नगर में महिला संगठन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष शैलेंद्र पटेल ने की, संवर्धन जिला मीडिया प्रभारी पप्पू वर्मा ने किया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मंच सुश्री दीपमाला कुशवाहा एवं पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह जैकी जी मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश सचिव लाखन पटेल शामिल हुए। मुख्य अतिथि दीपमाला कुशवाहा ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन



अनुप्रिया पटेल के निर्देश पर महिला संगठन की समीक्षा की जा रही है। अपना दल एस सामाजिक न्याय, महिला सम्मान व सुरक्षा के लिए

निरंतर संघर्ष कर रहा है। उन्होंने कहा कि बहन अनुप्रिया पटेल देश में सामाजिक न्याय की अग्रदूत के रूप में संघर्ष कर रही हैं, हमें उनका साथ देना होगा। उन्होंने बताया कि त्योहार के बावजूद बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता बैठक में पहुंचीं। जिला अध्यक्ष शैलेंद्र पटेल व जैकी जी ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस दौरान कांति कुशवाहा जिलाध्यक्ष महिला मंच, वृजेश पाल, योगेंद्र सिंह राणा, राजू पटेल, गुलाब सिंह, दीपांशु पटेल, दीपू पटेल, राहुल कुमार उर्फ जालिम, अतीश पटेल, डॉ. एनआर शर्मा, गोवर्धन पटेल, अशोक पटेल, अरुण पटेल, आलोक पांडेय, सुरेश पटेल सहित सैकड़ों पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।

पिंजरे में कैद हुआ नर गुलदार, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस

अफजलगढ़/बिजनौर (सब का सपना):- जनपद के थाना क्षेत्र के गांव अगवानपुर में बिरला फार्म चक रोड के पास किसान नायब सिंह के खेत में वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में मंगलवार देर रात एक नर गुलदार कैद हो गया।



है और उसकी उम्र करीब आठ से नौ वर्ष है। उन्होंने बताया कि गुलदार को पकड़ने के लिए किसान नायब सिंह के खेत में 22

अगस्त को पिंजरा लगाया गया था। गुलदार के पकड़े जाने के दौरान वन रक्षक अंकित चौहान, मुजीबुर्रहमान समेत वन विभाग

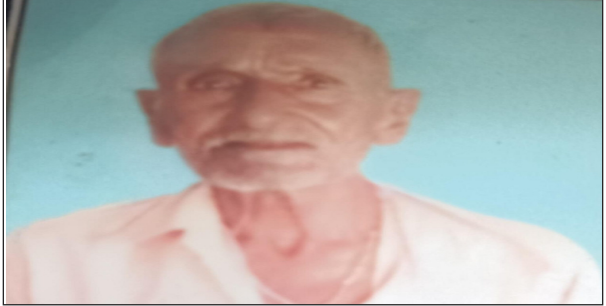
की टीम मौके पर मौजूद रही। गुलदार के पकड़े जाने से क्षेत्र के ग्रामीणों में व्याप्त दहशत कुछ कम हुई है।

आजादी से आज तक नहीं बना रास्ता, मौत के आगोश में समाया वृद्ध, ग्रामीणों में आक्रोश

सरकंडी के नंदन बाबा का डेरा में पक्की सड़क का इंतजार, बारिश में चारपाई पर ढोया गया शव



असोथर/फतेहपुर (सब का सपना):- आजादी के दशकों बाद भी गांव तक पक्की सड़क न पहुंचने का दर्श सरकंडी के मजरे नंदन बाबा का डेरा के ग्रामीण झेल रहे हैं। बारिश में कीचड़ से लथपथ रास्ता ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन गया है। मंगलवार रात इलाज के लिए अस्पताल ले जाने की तैयारी के दौरान 60 वर्षीय रामदेव निषाद की मौत हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि यदि गांव तक पक्का रास्ता होता तो समय पर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाना आसान होता। वृद्ध की मौत के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है और उन्होंने सरकार के मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के दावों पर सवाल उठाए हैं। नंदन बाबा का डेरा निवासी रामदेव निषाद पुत्र स्व. भर्दई मंगलवार को दिनभर अपने



कैमरे में कैद कर लिया। बारिश के कारण रास्ते की हालत इतनी खराब थी कि एंबुलेंस या निजी चार पहिया वाहन का गांव तक पहुंचना मुश्किल था। ग्रामीण मातादीन तिवारी, रजोल तिवारी, कल्लू तिवारी, सोनू निषाद, शंकर तिवारी, संतोष तिवारी, रामोतार, हरिश्चंद्र और विनय निषाद आदि ने कहा कि आजादी के बाद से अब तक गांव तक पक्का रास्ता नहीं बन सका है। चुनाव के दौरान सड़क बनवाने समेत मूलभूत सुविधाएं देने के वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव बीतते ही ग्रामीणों की समस्याएं फिर हाशिये पर चली जाती हैं। ग्रामीणों ने कहा कि सड़क न होने से केवल आवागमन ही प्रभावित नहीं होता, बल्कि बीमारी और आपात स्थिति में लोगों की जान पर भी बन आती है। ग्रामीणों ने कहा कि सरकार

नवागत लोकप्रिय पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई को एमआर पाशा ने दी गुलदस्ता देकर बधाई



देखने को मिला है इसको देखते हुए एसपी साहब जनता के प्रति अच्छा व्यवहार व पीडितों की शिकायत को गंभीरता से लेकर निस्तारण कर रहे हैं। एमआर पाशा ने एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई को दिव्यांगों की समस्याओं से अवगत कराया। नवागत लोकप्रिय पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने आवागमन

दिया है। कि जल्द ही आपको सभी समस्याओं का निस्तारण कराया जाएगा। और मैं अपने स्तर से बिजनौर के सभी जनपद के थाना प्रभारियों व पुलिस क्षेत्रीय अधिकारियों को अवगत कराऊंगा। मैं आपसे आशा करता हूं कि किसी भी राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन के कार्यकर्ता, पदाधिकारियों का शोषण

नहीं किया जाएगा। अगर कहीं भी शोषण किया जाता है तो संबंधित थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर शहजाद गोविंदपुर वाले, नकुल कुमार, सुशील कुमार, शाहे आलम, मोहम्मद इकराम, मोहम्मद आजम, मास्टर अफजाल, नसीम अहमद, सनावर, अनुज वर्मा आदि मौजूद रहे।

म	स्त		स	ला	ह	का	र		क	ल
		५					५	५		



‘धुरंधर 2’ के साथ वलैश पर यश का बड़ा बयान ‘टॉक्सिक’ के पोस्टपोन पर भी बोले एक्टर

साउथ सुपरस्टार यश इन दिनों अपनी फिल्म ‘टॉक्सिक ए फेयरी टेल गोन अप्स’ को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म की रिलीज को लेकर पहले रणवीर सिंह की ‘धुरंधर: द रिवेंज’ के साथ वलैश की बात सामने आई थी। अब यश ने इस पूरे मामले पर अपनी राय दी है।

फिल्म हुई बार-बार पोस्टपोन फिल्म ‘टॉक्सिक’ पहले 19 मार्च 2026 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन मिडिल ईस्ट में बनी अनिश्चितता के चलते इसकी रिलीज 4 जून कर दी गई। इसके बाद फिल्म की रिलीज फिर टाल दी गई। अब हाल ही में इंडिया टीवी के शो ‘आप की अदालत’ में यश ने फिल्म की रिलीज टालने और बॉक्स ऑफिस वलैश को लेकर खुलकर बात की।

100-200 करोड़ खाने का डर नहीं

यश ने साफ कहा कि फिल्म की रिलीज आगे बढ़ाने का फैसला इस डर से नहीं लिया गया कि बॉक्स ऑफिस पर 100 या 200 करोड़ रुपये का नुकसान हो जाएगा। उनके लिए यह फैसला पैसे या अहंकार का नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का था। यश ने कहा कि अगर वह सिर्फ अपनी इमेज बचाने या किसी को कुछ साबित करने के लिए फिल्म को उसी तारीख पर रिलीज करते, तो वह असली अहंकार होता। उनके लिए सबसे जरूरी यह था कि वह दर्शकों से किया हुआ अपना वादा पूरा कर पा रहे हैं या नहीं। एक्टर ने कहा कि उनका सबसे बड़ा डर फिल्म को लेकर था। अगर उन्हें लगता है कि वह दर्शकों को वह फिल्म नहीं दे पा रहे हैं, जिसका उन्होंने वादा किया था, तो वह पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ना पसंद करेंगे।

कभी जानबूझकर किसी फिल्म से वलैश नहीं किया

बॉक्स ऑफिस वलैश को लेकर यश ने यह भी

साफ किया कि उन्होंने कभी जानबूझकर किसी दूसरी फिल्म के साथ अपनी फिल्म का वलैश नहीं किया। उन्होंने कहा, ‘जो भी वलैश आप बोल रहे हैं, उसमें मैं सीधे जाकर कभी वलैश में नहीं आया। मेरी

डेट पहले

अनाउंस होती है

और उसके बाद

अगर कोई

फिल्म आती है,

तो वो वलैश हो

जाता है।’ यश

ने यह भी कहा

कि उन्हें जिंदगी

में कुछ खोने का

डर नहीं है।

उन्होंने कहा,

जिंदगी में मुझे

खोने का कुछ है

ही नहीं, तो मुझे

डर है ही नहीं।’



टॉक्सिक के किरदार नादिया को कियारा ने बताया मुश्किल

यश की फिल्म ‘टॉक्सिक : ए फेयरी टेल फॉर गोन अप्स’ में कियारा आडवाणी ने नादिया का किरदार निभाया है। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर फिल्म से जुड़ी पोस्ट साझा की। इसमें उन्होंने एक अभिनेत्री के तौर पर अपने किरदार से जुड़े अनुभव साझा किए हैं।

कियारा के लिए फिल्म ‘टॉक्सिक’ उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म है। इस फिल्म में नादिया का किरदार निभाने और उसकी मांग पर कियारा ने काफी कुछ लगा। एक्ट्रेस ने लिखा फिल्ममें हमें उस दुनिया में ले जाने का एक खूबसूरत तरीका होती हैं जिनमें हम असलियत में नहीं जा सकते। हर नया किरदार, हर नया सेट, हर चुनौती आपको कुछ ऐसा सिखाती है। आपकी क्षमताओं के बारे में बताती है। इस किरदार ने मुझे

अपरिचित और मुश्किल चीजों के साथ भी सहज होना सिखाया। नया किरदार आपको नए कौशल, नए रोमांच और उस जुनून के लिए जो आपको बार-बार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। मेरे लिए ग्रोथ का मतलब हमेशा उस काम के लिए हामी भरना है जिसे करने से आपको थोड़ा डर लगे। यह किरदार नई स्किल्स, नए एडवेंचर्स और उस जुनून के नाम, जो आपको बार-बार नई चीजों में डूबने के लिए तैयार रखता है।

फिल्म ‘टॉक्सिक’ के वक्त प्रेगनेंट थीं कियारा

फिल्म से जुड़े एक इवेंट में अभिनेता यश ने कियारा की खूब तारीफ की थी। उन्होंने कहा, ‘मेरा यह सोचना है कि कियारा एक बेहद पेशेवर अभिनेत्री हैं। जब वह इस फिल्म के लिए कास्ट हुई थीं तो मैं काफी चिंतित था, क्योंकि यह फिल्म काफी चुनौतीपूर्ण है पर कियारा ने जिस तरह फिल्म के लिए खुद को समर्पित किया है। वह देखना बेहद शानदार रहा।

कब रिलीज होगी ‘टॉक्सिक’

फिल्म ‘टॉक्सिक’ में यश मुख्य भूमिका में हैं। उनके अलावा कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरेशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत जैसी अभिनेत्रियां भी इसमें नजर आएंगी। यह फिल्म 26 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसे ग्लोबली कई भाषाओं में रिलीज किया जा रहा है।



एटली ने द ओडिसी को बताया ज़बरदस्त एपिक फिल्म, कहानी, विजुअल्स और संगीत की जमकर तारीफ

फिल्ममेकर एटली ने ‘द ओडिसी’ की जमकर तारीफ करते हुए इसे एक ऐसा सिनेमाई अनुभव बताया है, जो सामान्य फिल्मों से कहीं आगे जाता है। एटली ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक इमोशनल नोट शेयर करते हुए क्रिस्टोफर नोलन की कहानी कहने की शैली, फिल्म के विजुअल्स, सिनेमैटोग्राफी और लुडविग

गोरानसन के संगीत की प्रशंसा की है।

अपने अनुभव को साझा करते हुए एटली ने अपनी पोस्ट में लिखा है, ‘कुछ फिल्में आप देखते हैं। कुछ फिल्मों की आप तारीफ करते हैं। और फिर, बहुत कम ऐसी फिल्में होती हैं जो आपको पूरी तरह किसी दूसरी जगह ले जाती हैं। ‘द ओडिसी’ ने मेरे साथ यही किया।’ उन्होंने नोलन की कहानी को ‘अद्भुत’ बताया हुए यह भी लिखा है कि फिल्म के विजुअल्स अपनी अलग भाषा बोलते हैं और कैमरा भी कहानी सुनाने वाले एक किरदार की तरह महसूस होता है। इसी के साथ लुडविग गोरानसन के संगीत की तारीफ में लिखा है कि यह संगीत सिर्फ फिल्म के साथ चलता नहीं है, बल्कि आपकी धड़कनों में उतर जाता है। एटली ने आगे यह भी लिखा है कि फिल्म में ऐसा एड्रेंनालिन और इमर्सिव प्रभाव है, जैसा उन्होंने थिएटर में बहुत कम महसूस किया है। उन्होंने लिखा कि सबसे ज्यादा उनके साथ जो चीज रह गई, वह बेहद व्यक्तिगत थी, जब दर्शक पूरी तरह फिल्म के अनुभव में डूब जाता है, ‘तभी एक सच्ची एपिक फिल्म बनती है। उन्होंने लिखा है, ‘फिल्म को अपने चारों ओर घेरकर, अपने ऊपर हावी होने दें।’

पुलकित सम्राट को पहचानना हुआ मुश्किल इस वजह से घटा ढाई किलो वजन

पुलकित सम्राट ने सोमवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर साझा की। इस तस्वीर में पुलकित इतने बदले हुए नजर आए कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया। इस स्टोरी के जरिए पुलकित ने फैस को बताया कि वो इ दिनों बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। जानिए पुलकित ने और क्या कहा?

स्टोरी में क्या बोले पुलकित

एक्टर ने बताया कि वो बीते कुछ दिनों से मलेरिया से पीड़ित हैं। अभिनेता ने बताया कि इस बीमारी की वजह से उनका वजन कम हो गया है। पुलकित ने तस्वीर शेयर कर जानकारी दी कि बीते कुछ दिनों में उनका ढाई किलो वजन कम हो गया। हालांकि, अभिनेता ने पॉजिटिविटी पर बात करते हुए कहा कि वह अपना वजन फिर से बालेंस कर लेंगे। इसके साथ ही पुलकित ने एक तस्वीर भी साझा की जिसमें वह बेहद कमजोर नजर आ रहे हैं। कुछ समय पहले इंटरव्यू में पुलकित ने सलमान खान को लेकर जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि अपनी पहली फिल्म की रिलीज के वक्त हर नए कलाकार की तरह वह भी घबराए हुए थे, लेकिन तब सलमान खान की बातों ने स्टारडम के प्रति उनका नजरिया बदल दिया था।

पुलकित का वर्कफ्रंट

पुलकित को आखिरी बार नेटफिलक्स सीरीज ‘ग्लोरी’ में देखा गया था। करण अश्वामन और कनिष्क वर्मा के निर्देशन में बनी इस स्पॉर्ट्स एक्शन ड्रामा में दिवेंद्रु और सुविंदर विक्की भी अहम भूमिकाओं में थे। सीरीज को क्रिटिक्स और दर्शकों, दोनों से ही अच्छे रिव्यू मिले। दूसरी तरफ उनकी आखिरी फिल्म ‘राहु –केतु’ सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।

रोमांच बढ़ाएंगी ‘बबीता सिंह रिपोर्टिंग’, हत्या की गुत्थी सुलझाती दिखेंगी निमिषा सजयन

सोमवार को अभिनेता बरुन सोबती की अगली फिल्म ‘बबीता सिंह रिपोर्टिंग’ की रिलीज डेट मेकर्स ने जारी की। यह एक इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा पर आधारित है। फिल्म एक हत्या के केस और उसकी तहकीकात से जुड़ी है। इसे ‘पाताल लोक’ के मेकर्स ने ही बनाया है।

क्या है ‘बबीता सिंह रिपोर्टिंग’ की कहानी?

फिल्म ‘बबीता सिंह रिपोर्टिंग’ में मुख्य किरदार बबीता सिंह नाम की एक एसआई का है, जिसके पास एक हत्या का केस आता है। इस दौरान उसका सामना कई रहस्यों और खतरों से होता है। फिल्म की कहानी एसआई के जीवन की मुश्किलों पर बात करती है। इस पूरे सफर में वह खुद की खोज भी करती है। फिल्म ‘बबीता सिंह रिपोर्टिंग’ 28 अगस्त से प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। फिल्म का निर्देशन अबीएका पंडित ने और लेखन अमिता व्यास ने किया है। एसएसआई बबीता सिंह उर्फ बेबी का रोल निमिषा सजयन ने निभाया है। वहीं बरुण सोबती और अश्वामन पुष्कर भी अहम भूमिकाओं में हैं।



अभिनेत्री होने पर शर्मिदा किया जाता था, अनुपमा ने खोले एक्स के राज

इन दिनों अनुपमा परमेश्वरन अपने व्यक्तितगत जीवन के लेकर चर्चाओं में हैं। अपने पुराने रिलेशनशिप और उससे जुड़े दर्द के बारे में अब वह खुलकर सामने आ रही हैं। उन्होंने अपने तकलीफ भरे रिश्ते के बारे में काफी कुछ बताया। जानें क्या कहा एक्ट्रेस ने... इससे कई दिनों से एक्ट्रेस अनुपमा परमेश्वरन ने ध्यान वर्मा के यूट्यूब चैनल पर रिश्ते को लेकर कई खुलासा किये हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह उनके पार्टनर ने रिलेशनशिप के दौरान उनका उत्पीड़न किया। अनुपमा ने बताया एक समय मैं ग्यारह बच्चे पैदा करने का सपना देखती थी। मगर इस रिश्ते के बाद अब मैं बच्चे ही नहीं चाहती। मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे आत्मविश्वास और पेशेवर उपलब्धियों के लेकर कई बार मुझे बहुत बुरा महसूस करवाया। इस रिश्ते ने मेरे निजी जीवन और करियर दोनों में लिए गए मेरे कई फैसलों को प्रभावित किया। मुझे कई बार एक महिला होने और यहां तक कि मेरे एक्टर होने पर भी शर्मिदा महसूस कराया गया। अपनी बातचीत में आगे अनुपमा परमेश्वरन ने कहा, ‘पीरियड्स का पहला दिन हो, पांचवां दिन हो, दसवां दिन हो, पंद्रहवां दिन हो, बीसवां दिन हो, पच्चीसवां दिन हो, कोई भी दिन हो। अगर आप किसी व्यक्ति से उसकी गलती के बारे में पूछें, तो वो कहेगा – ‘अरे, आपको पीएमएस हो रहा है, आपका पीरियड अभी आना बाकी है।’ उसके ऐसा कहने पर मुझे बहुत शर्म आती थी। मुझे औरत होने पर

बहुत बुरा लगता था। मुझे अपनी सारी उपलब्धियों पर ही बुरा लगने लगा था।’ ‘परधा’ इवेंट में रोने की वजह बताई अगस्त 2025 में अनुपमा डायरेक्टर के साथ अपनी फिल्म ‘परधा’ का प्रमोशन कर रही थीं। प्रेस के साथ सवाल-जवाब के दौरान वह अचानक भावुक हो गईं और रोने लगीं। उनकी टीम ने उन्हें शांत कराया और पानी दिया। जब पत्रकार उनसे बार-बार पूछने लगे कि वह इतनी भावुक क्यों हो रही हैं? तो अनुपमा ने बात को टालते हुए कहा था कि महिला-केंद्रित फिल्म को शूट करना और उसका प्रमोशन करना आसान नहीं था। अब हाल ही में उस घटना को याद करते हुए अनुपमा ने कहा, ‘हालात कितने भी मुश्किल हों पर मैं मैं ऐसी नहीं हूँ कि स्ट्रेज पर ही रोने लूँ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुझे वो सबसे बुरी बातें कहीं गईं, जो कोई महिला सुनना नहीं चाहती। जिस इंसान को मेरी रक्षा करनी चाहिए थी, वही मुझे अंदर से तोड़ रहा था।’

